सर्वहारा अधिनायकत्व और जनता का जनवादी राज्य के कुछ प्रश्न

विजय सिंह

लेनिन अपनी रचना *राज्य और क्रान्ति* में कहते हैं, "केवल वह ही मार्क्सवादी है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को आगे बढ़ाकर *सर्वहारा अधिनायकत्व* की मान्यता तक ले जाता है। यह उस सुस्पष्ट अन्तर को रेखांकित करता है जो एक मार्क्सवादी और साधारण पेट्टी बुर्जुआ और (यहां तक कि बड़े) बुर्जुआ के बीच है। यह वह पारस पत्थर है जिस पर मार्क्सवाद की *वास्तविक* समझ एवं मान्यता को परखा जाता है।"

नव जनवाद एवं जनता के जनवाद की उत्पत्ति की जड़ें 1933 के आरम्भ में नाजीवाद के सत्ता में आने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन को प्राप्त अनुभवों में निहित हैं। 1935 में कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय (संक्षेप में कोमिन्टर्न) की सातवीं कांग्रेस ने फासीवाद के उभार को संज्ञान में लेने, उसका मुकाबला करने और उसे कुचलने का निश्चिय किया। यह हमें स्टालिन के जीवन के अन्तिम दिनों में एवं उसके बाद जनता के जनवादी राज्यों में हुए राजनैतिक विकासक्रम को अवस्थित करने में मदद करता है।

1935 में कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय की सातवीं कांग्रेस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी प्रक्रिया के प्रति नया नजरिया अपनाने के साथ एक तीखा मोड़ आया। नाजीवाद के सत्तारोहण ने फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई के शुरूआती दौर में अपनाई गई रक्षात्मक रणनीति और कार्यनीति को बदलने को मजबूर कर दिया। स्टालिन, दिमित्रोव कोमिन्टर्न के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टियों ने नया दृष्टिकोण और कार्यशैली अख्तियार किया। कोमिन्टर्न 1935 से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सलाह दे रही थी कि जापानी साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष की राष्ट्रीय क्रान्तिकारी प्रक्रिया में एक गैर–सोवियत जनवादी दृष्टीकोण की आवश्यकता है। स्पेन में, स्पेनी गणतंत्र पर हिटलर और मुसोलिनी की मदद से किया गया सैन्य आक्रमण स्पेन की समस्त फासीवाद विरोधी शक्तियों के एक व्यापक पापुलर फ्रन्ट (जन मोर्चा) की मांग कर रहा था। जॉश डियाज के नेतृत्व में स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1937 से यह तर्क देना शुरू कर दिया था कि नये तरीके की संसदीय गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के दौरान सामंती एवं वित्तीय कुलीनतंत्र का नाश किया जा सके।[1] इतिहासकारों ने रेखांकित किया कि कम्युनिस्ट आन्दोलन में 'जनता का जनवादी राज्य' का उद्‌भव 1931–39 के बीच घटित हुई स्पेनिश क्रान्ति से हुआ था, जहां एक नये प्रकार का संसदीय गणराज्य राज्यसत्ता का नेतृत्व करेगा, जिसमें राजनैतिक शक्ति फासीवाद–विरोधी गठबंधन में केन्द्रित होगी, जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा में भागीदार बुर्जआ वर्ग के वामपंथी हिस्से भी शामिल रहेंगे।[2] चीन में जापानी साम्राज्यवाद के प्रतिरोध की आवश्यकता ने सोवियत संघ एवं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को क्वोमिन्टांग के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए प्रेरित किया, जो 1936 की 'सियान' परिघटना के बाद फलीभूत हुआ। माओ द्वारा 1938 में लिखित 'नई अवस्था' में उन्होंने स्वीकार किया था कि जापान के विरूद्ध संयुक्त मोर्चा में च्यांग काई शेक सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और कोमिन्टर्न की दूरगामी एकता को जन राजनैतिक समितियों द्वारा राजनैतिक जनवाद को हासिल करना प्राथमिक कदम बताया। माओ ने 1939 में 'नव बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति' की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो एक सामन्तवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्ति का आगाज करेगी, जिसका नेतृत्व सर्वहारा वर्ग करेगा, जिसकी धार मुख्यतः जापानी साम्राज्यवाद के विरूद्ध होगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जनवरी 1940 से प्रक्षेपित नव जनवाद एक सुविज्ञात तथ्य है जो कम्युनिस्ट पार्टी और क्वोमिन्टांग के संयुक्त मोर्चे द्वारा चिन्हित हुआ जिसमें माओ एवं पार्टी के अन्य नेताओं ने चीनी सरकार में हिस्सा लिया। 'नव जनवाद' 1945 के बाद की अवधि में भी सीपीसी की मांग बनी रही।[3] बाद में जब क्वोमिन्टांग के साथ संयुक्त मोर्चे की सम्भावना समाप्त हो गई और जब सीपीसी एक मजबूत अवस्था में आ गई, माओ ने जनता के जनवाद की मांग का नारा दिया।

नाजीवाद की पराजय के पश्चात मध्य एवं दक्षिण–पूर्वी यूरोप में जो नए राज्य स्थापित हुए, वे प्रारम्भिक तौर पर नव जनवादी कहे गए। फासीवाद और भूस्वामी शक्तियों के समर्थकों की पराजय के पश्चात तथा समाजवाद की दिशा में कदम बढ़ाने के साथ, इन देशों में 'जनता के जनवादी राज्य' का परिदृश्य स्पष्ट हो गया। दिसम्बर 1948 में बुल्गारिया की वर्कर्स पार्टी की पांचवीं कांग्रेस की राजनैतिक रिपोर्ट में ज्यार्जी दिमित्रोव ने देश में जनता के जनवादी राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जहां उन्होंने बुल्गारिया में सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया और जनता के जनवाद के दायरे में समाजवादी निर्माण की आवश्कता प्रतिपादित की।[4] और कुछ माह पश्चात, चीन में क्रान्ति–पूर्व बेला पर, जुलाई 1949 में माओ ने 'जनता के जनवादी अधिनायकत्व' के बारे में अपना लेख प्रकाशित किया। इसने पहले की 'नव जनवाद' की अवधारणा को खारिज कर दिया जो कि अब पुरानी हो चुकी थी। स्टालिन ने 22 फरवरी 1950 में सोवियत अर्थशास्त्रियों के साथ अपनी चर्चा के दरम्यान पूर्वी यूरोप और चीन में जनता के जनवादी

राज्य के बीच के अन्तर पर गम्भीर पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया था। उन्होंने सूत्रांकित किया था कि यूरोपीय जनता के जनवादी राज्य 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' के कार्यभार को पूरा कर रहा है, जबकि चीन में अब भी ऐसा नहीं है। वहां जनता का जनवादी राज्य सर्वहारा एवं किसानों के जनवादी अधिनायकत्व के समतुल्य है।

पूर्व की 'जनता की जनवादी' संरचनाएं – चीन, कोरिया, वियतनाम – को ऐसा समझा गया जैसे कि वे दो अवस्थाओं से होकर गुजरेंगी। पहले तो एक साम्राज्यवाद–सामंतवाद विरोधी क्रान्ति से और फिर दूसरी अवस्था में समाजवाद की ओर जाने के लिए सर्वहारा के अधिनायकत्व के कार्यभार के प्रश्न को आगे ले जाएंगी। यह समझदारी यूरोपीय देशों की 'जनता की जनवादी संरचनाओं के अनुभवों से हासिल की गई थी।

मध्य एवं दक्षिण–पूर्वी यूरोप में क्रान्तिकारी प्रक्रिया का प्रारम्भ साम्राज्यवाद–फासीवाद विरोधी आन्दोलन से हुआ था जिसमें सामन्तवाद विरोधी आन्दोलन गुंथा हुआ था। वहां 'जनता के जनवाद' ने सर्वहारा का पूर्ण अधिनायकत्व तुरन्त ही स्थापित नहीं किया था और न ही समाजवाद के लिए सीधा संघर्ष शुरू किया था, क्योंकि उनका सर्वप्रथम मुख्य कार्यभार फासीवाद को पराजित करना, राष्ट्रीय और जनवादी स्वतंत्रता प्राप्त करना था, नाजियों द्वारा थोपी गई गुलामी, भूदासता को खत्म करना था, नाजी हुकुमत के कुप्रभावों को समाप्त करना था और सामन्तवाद के अवशेषों का समाप्त करना था। तमाम देशों में जनता के जनवाद की प्रारम्भिक अवस्थाओं में राज्य सत्ता में मध्यम बुर्जुआ ने भी साझेदारी की थी।[7] 1948–49 की एक निश्चित परिस्थिति में, इन राज्यों में सर्वहारा और किसानों के अधिनायकत्व की अवस्था आगे बढ़कर सर्वहारा के अधिनायकत्व की दिशा में विकसित होना शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य समाजवाद का निर्माण था। यह लेनिन की इस समझदारी के अनुरूप था कि जनवादी क्रान्तियां बिना किसी व्यवधान, रुकावट के समाजवाद की दिशा में परिवर्तित हो सकें। समाजवाद की दिशा में बढ़ते हुए कदमों में मध्यम बुर्जुआ एक रुकावट बनना शुरू हो गया था और उसका जनता के समक्ष भंडाफोड़ करना था तथा उसे राज्य सत्ता से बेदखल करना था। इस तरह से जनता के जनवाद की दूसरी अवस्था, जो कि समाजवादी क्रान्ति थी, क्रमशः सम्पन्न हुई।[8]

दूसरे चरण में, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था – जिन देशों में जनता का जनवाद था – उन्हें समाजवादी नहीं माना गया, बल्कि वे एक संक्रमणकालीन चरित्र के थे, जहा सम्पत्ति के तीन तरह के स्वरूप थे :

> उत्पादन के साधनों पर राष्ट्रव्यापी समाजवादी मालिकाना ; सहाकरी स्वामित्व जिसका मुख्य स्वरूप समाजवादी था और उत्पादन के साधनों पर निजी मिल्कियत, जो दो प्रकार की थी, पहला, किसानी करने वालों के हाथ में, शिल्पकारों के पास, कारीगरों के पास, जो व्यक्तिगत श्रम पर आधारित था और दूसरा, शोषण पर आधारित निजी पूंजीवादी मिल्कियत। इनमें से प्रत्येक देश में तीन प्रकार के बुनियादी सामाजिक–आर्थिक ढांचे थे – समाजवादी, लघु माल उत्पादन और पूंजीवादी। उद्योग में समाजवादी सेक्टर नेतृत्वकारी हैसियत रखता था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली था। अन्त में, संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चारित्रिक लक्षण यह था कि जनता के जनवादी देशों में अभी भी वहां शोषक (बुर्जुआजी, कुलक) मौजूद थे।[9]

यूरोप के 'जनता के जनवादी' देशों में उपरोक्त प्रकार के सम्पत्ति संबंध प्रायः स्टालिन काल की समाप्ति तक वैसे ही बने रहे।

यद्यपि यूरोप के जनता के जनवादी देशों को कहने में 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' वाले देश कहा जाता था, किन्तु वस्तुतः वे न तो समाजवादी समझे जा सकते थे, न ही उनकी अर्थव्यवस्था को वैसा समझा जा सकता था क्योंकि वहां कुछ शोषक वर्ग, मध्यम बुर्जुआ एवं ग्रामीण बुर्जुआ, अभी भी मौजूद थे। इन 'जनता के जनवादी' देशों को संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं का ही माना जाता रहा, जो समाजवादी निर्माण के लिए की दिशा में शायद की कदम उठाना शुरू कर पाए थे।

उक्त देशों का वर्गीकरण ऐसे जनवादी देशों में किया जाता रहा जो समाजवादी सोवियत संघ से नत्थी थे। जैसा कि 'जदानोव' ने सितम्बर 1947 में कम्युनिस्ट इंफारमेशन ब्यूरो (कम्युनिस्ट सूचना ब्यूरो) में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर उद्घाटन भाषण में इन देशों को 'सोवियत संघ एवं जनवादी देशों' कह कर सम्बोधित किया था।[10] कम्युनिस्ट इनफारमेशन ब्यूरो की नवम्बर 1949 की बैठक में इस चारित्रिक वर्गीकरण की पुष्टि भी हो गई थी।[11] इसी वैचारिक दिशा के अनुरूप जी मैलेन्कोव ने 1952 में उस अन्तर को स्पष्ट किया था जो यूरोप के 'जनता के जनवादी' देशों एवं समाजवादी सोवियत संघ के शिविर के बीच था। उन्होंने यह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस में अपने वक्तव्य में कहा था।[12]

1952 में स्टालिन ने 'सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक समस्याएं' रचना में यह तर्क प्रतिपादित किया था कि साम्राज्यवाद के विरूद्ध एक समाजवादी खेमा (कैम्प) उठ खड़ा हुआ है : चीन तथा यूरोप की 'जनता की जनवादी' सत्ताओं ने पूंजीवादी व्यवस्था से अपना नाता तोड़ लिया है और उन्होंने सो. वितय संघ के साथ मिलकर पूंजीवादी खेमे के विरूद्ध एक शक्तिशाली एवं संगठित समाजवादी खेमे निर्माण कर लिया है।[13]

स्टालिन समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के बाजार के बारे में

बोल रहे थे; उनका आशय कतई यह नहीं था कि 'जनता के जनवादी' देशों में से कोई भी, वह चाहे पश्चिम का हो या पूर्व का, समाजवादी राज्य बन गया है; वे अब भी जनवादी के दायरे में हैं।

यह मैलेन्कोव की सीपीएसयू की 19वीं कांग्रेम में दिए गए भाषण से भी स्पष्ट हो जाता है कि अ) जैसा कि उन्होंने वर्गीकृत किया था कि जनता के जनवादी वे देश हैं जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था से अपना सम्बंध विच्छेद कर लिया है, शान्ति एवं जनवाद के लिए सोवियत संघ के साथ एक खेमा बना लिया है, जो साम्राज्यवादी खेमे के विरूद्ध है; ब) विश्व साम्राज्यवाद के विरूद्ध उसकी अर्थव्यवस्था के समानांतर एक आर्थिक बााजार निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो साम्राज्यवाद के विरूद्ध शान्ति और जनवाद के खेमे के देशों के साझा बाजार द्वारा निर्मित है।

चीन एवं यूरोप के जनता के जनवादी देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था से अपना सम्बंध विच्छेद कर लिया है, तथा सोवियत संघ के साथ साम्राज्यवादी खेमे से संघर्षरत शान्ति और जनवाद के ल क्ष्य हेतु एकमात्र एक और शक्तिशाली खेमा निर्मित किया हैं।

दो परस्पर विरोधी खेमों की निर्मिति हो गया और समानांतर दो आर्थिक बाजार अस्तित्व में आ गए : एक उन देशों का बाजार जो शान्ति और जनवाद के खेमे में हैं और दूसरा उन देशों का बाजार जो हमलावर साम्राज्यवादी खेमे में हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक परिणामस्वरूप एकल विश्व बाजार का विघटन हो गया है। यह उसका आर्थिक फलीभूत निष्कर्ष है।[14]

स्टालिन के अन्तर्गत सोवियत लेखकों, जैसे ए.आई. सोवोलोव ने हमेशा समाजवादी सोवियत संघ, पश्चिमी जनता के जनवादी देशों, जो सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना कर चुके थे और समाजवादी निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चुके थे तथा पूर्व के जनता के जनवादी देशों में अन्तर को रेखांकित किया जहां अभी किसानों और मजदूरों का अधिनायकत्व था, जो अभी भी राष्ट्रीय पूंजी से सम्बद्ध थे, जहां सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना होनी अभी शेष थी और समाजवादी निर्माण के रास्ते पर चलना अभी प्रारम्भ ही करना था। ये अन्तर सोवियत संघ की कम्युनस्टि पार्टी की 1956 की बीसवीं कांग्रेस के बाद धुंधले पड़ गए।

II

> "जहां बुर्जुआ जनवाद पूंजी का अधिनयाकत्व होता है, जिसमें एक अल्पसंख्यक बड़ा पूंजीपति वर्ग मेहनतकशों की बहुसंख्या का शोषण करता है, वहीं जनता का जनवाद सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना करता है, उसके कार्य पूरा करता है, जो मेहनतकशों की व्यापक बहुसंख्या के हितों की पूर्ति करता है और वस्तुतः एक व्यापक एवं सम्पूर्ण जनवाद की अनुभूति करवाता है, जिसे समाजवादी जनवाद कहते हैं"। (दिमित्रोव)

किसानों एवं सर्वहारा के अधिनायकत्व से सर्वहारा के अधि ानायकत्व तक के संक्रमण की ही तरह फासीवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी एवं सामन्तवाद विरोधी जनता के जनवादों का संक्रमण (एवं रूपांतरण) समाजवादी निर्माण के प्रारम्भिक चरण तक होना हमेशा प्रायः शान्तिपूर्ण नहीं होता है। जैसा कि यूगोस्लाविया के उद्धरण से स्पष्ट है, जिसने अपने आपको सोवियत संघ के समाजवादी खेमे और जनवादी राज्यों से बाहर कर लिया था।

इसका आर्थिक आधार यह था कि यूगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी ने पूंजीवादी तत्वों के राष्ट्रीयकरण – बुर्जआजी के बड़े बहुसंख्या को समाप्त करना, कुलकों का खात्मा करना, जो कि सामूहिक एवं सहकारी कृषि की एक आवश्यक शर्त थी, जिसे गरीब एवं मध्यम किसानों द्वारा बनाया जाना था, का भीषण विरोध किया। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) और युगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी के पत्राचारं, जिस पर स्टालिन एवं मोलोटोव के हस्ताक्षर हैं, में ये प्रश्न उठाए गए हैं। 27 मार्च 1948 में में वे कह रहे हैं :–

> "युगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीवाई) में वर्ग संघर्ष की चेतना का अनुभव नहीं हो पा रहा है। गांवों एवं शहरों में पूंजीवादी तत्वों की बढ़ोतरी पूरी शिद्दत से हो रही है और पार्टी नेतृत्व इन तत्वों पर लगाम लगाने की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सीपीवाई दरअसल पूरी तरह से बर्नस्टीन, बोलमार और बुखारिनसे उधार लिए गए समाजवादी व्यवस्था द्वारा पूंजीवादी तत्वों को शान्तिपूर्ण ढंग से समाहित करने की अवसरवादी एवं पतित सिद्धान्त का पालन कर रही है।"[15]

13 अप्रैल 1948 को टीटो और कार्डलेज के हस्ताक्षर से जारी पत्र में युगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका उत्तर दिया जिसमें इन आरोपों को अस्वीकार कर दिया गया था। पुनः 4 मई 1948 के अपने पत्र में स्टालिन और मोलोटोव ने अपने तर्क को जारी रखा जिसमें उन्होंने युगोस्लावाई पथ को सोवियत संघ के अनुभव से विपरीत बताया और इस पर जोर दिया कि सीपीवाई पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के दरम्यान वर्ग संघर्ष के तीखे होने की मार्क्सवादी–लेनिनवादी दिशा का पालन नहीं कर रही है। स्टालिन और मालोतोव ने लेनिन का उद्धृत किया :

> 1920–21 में लेनिन का वक्तव्य है कि "जब हम छोटी सम्पत्ति के मालिकों के देश में रहते हैं तो रूस जैसे देश में कम्युनिज्म की अपेक्षा पूंजीवाद का आर्थिक आधार अधि ाक मजबूत पाते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने की व्यक्तिगत खेती प्रतिघण्टे, प्रतिदिन, प्रत्येक अवसर पर बड़े पैमाने पर जनता के स्तर पर पूंजीवादी और बुर्जुआ विचारों का उत्पादन करता रहता है।"

यह मात्र संयोग नहीं है कि युगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व वर्ग संघर्ष के प्रश्न एवं गांवों में पूंजीवादी तत्वों पर लगाम लगाने के सवाल की अनदेखी करती है। जो इससे भी खतरनाक है, वह यह कि यूगोस्लाविया के नेतृत्व के भाषणों में गांवों में वर्ग विभेद के बारे में कोई जिक्र तक नहीं होता, किसानों को पूरे समुदाय के एक वर्ग के रूप में देखा जाता है (जैसे उसमें वर्ग भेद, छोटा–बड़ा नहीं है) और गांवों में शोषक तत्वों की वृद्धि द्वारा उत्पन्न समस्याओं पर विजय प्राप्त करने हेतु पार्टी अपनी शक्तियों को गतिशील नहीं करती है।16

स्टालिन और मोलोटोव ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि यूगोस्लाविया में भूमि का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है और भूमि में निजी सम्पत्ति बनी रहने से, यह कुलकों के हाथ में केन्द्रित है, जो किराये के मजदूरों का शोषण करते हैं। इसलिए अगर हमें समाजवाद का निर्माण करना है तो वर्ग संघर्ष की अनदेखी नहीं की जा सकती है। अतः हमारे लिए आत्म संतुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।[17]

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) तथा अन्य पार्टियों की आलोचना की प्रतिक्रिया स्वरूप युगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी ने अति वामपंथी कार्यवाहियों का एक सिलसिला ही शुरू कर दिया, जिससे पूंजीवादी तत्व एवं ग्रामीण बुर्जुआ का नाश हो सके। इन कार्यवाहियों का चरित्र लोकरंजना था, क्योंकि सामूहिकीकरण की तैयारी के लिए पहले से उचित कदम नहीं उठाए गए थे, जैसा कि कृषि मशीनों का उत्पादन एवं उनकी आपूर्ति। अतः यह नीतियां सफल नहीं हो सकी।[18] युगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नया कृषि ढांचे का गठन किया, जिसमें सामूहिक फार्म सोवियत संघ की तरह गरीब–मध्यम किसान के द्वारा न बनाए जाकर ग्रामीण बुर्जुआजी एंव कुलकों को शामिल करके बनाया गया।[19]

1949 के अपने प्रस्ताव में यूगोस्लाविया की अवस्थिति के प्रश्न पर कम्युनिस्ट इनफारमेशन ब्यूरो ने कहा :

> कुलकों द्वारा जबरदस्ती बनाई और चलाई जा रही 'उत्पादक सहकारी समितियां' किसानी करने वाली जनता के शोषण का एक नया तरीका है। कुलक, जो कृषि मशीनों और औजारों के स्वामी हैं, गरीब किसानों का न केवल शोषण करते हैं, बल्कि इन तथाकथित सहकारी समितियों में उनके अपने कृषि फार्मों से अधिक क्रूर शोषण किया जाता है।[20]

यूगोस्लाविया में एग्रीकल्चर मशीन स्टेशन कृषि क्षेत्र में उत्पादन के साधनों एवं मशीनों का स्वामी होता था। 1950 में एक डिक्री द्वारा उन्हें भंग कर दिया गया। कहा गया कि उत्पादन के साधन उत्पादकों के पास ही होने चाहिए। इन स्टेशनों के ट्रेक्टर एवं अन्य मशीनें सहकारी समितियों (कोआपरेटिव) को स्थाई इस्तेमाल के लिए दे दी गईं। इस प्रक्रिया ने मालों के परिचलन के दायरे का देश में विस्तार कर दिया था। यह 1958 में सोवियत संघ एवं चीनी लोक गणराज्य में एक उद्धरण बन गया। यूगोस्लाविया ने समाजवाद का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें पूंजीवादी तत्व, कुलकों की सहकारी समितियों के साथ रह सकते हैं। एवं स्व–प्रशासन करने वाले उद्योग उपभोग की वस्तुओं – मालों का उत्पादन करते रह सकते हैं।

जैसा कि 1951 में यूगोस्लाविया के कुलकोंके अधीन सहकारी फार्म आंशिक तौर पर खत्म किए गए थे और काफी हद तक सम्पत्ति सम्बंधों एवं 28 मार्च 1953 की किसान सहकारी समिति के पुनर्गठन डिक्री के द्वारा उन्हें खत्म किया गया था। 1953 के अन्त तक यूगोस्लाविया में मात्र 1 258 किसानी सहकारी समितियां शेष रह गई थीं।[21]

यूगोस्लाविया एक ऐसे 'जनता के जनवादी राज्य' की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा था जो समाजवाद की ओर बेरोकटोक आगे बढ़ने से इन्कार कर रहा था और पूंजीवादी रास्ते को पुनर्स्थापित कर रहा था। कम्युनिस्ट इनफारमेशन ब्यूरो (कोमिनफार्म) ने 1949 में चिन्हित किया था कि 'जनता के जनवादी राज्य' की व्यवस्था उक्त देश में समाप्त प्राय है। अतः ऐसी परिस्थितियों में सर्वहारा के अधिनायकत्व के कार्यभार किसी भी प्रकार व्यवहार में लागू नहीं हो सकते।

III

> "वर्गीय शक्तियों के वर्तमा सम्बंधों को पूंजीवादी शक्तियां कुंठित करने हेतु भरसक प्रयास कर रही हैं, ताकि उत्पन्न अवस्थाएं उनके लिए अधिक लाभदायी हो सके। वे स्थिरता चाहते हैं ताकि वे जनता की जनवादी व्यवस्था में उपलब्ध अवसरों को पूंजीवादी तत्वों के उपयोग हेतु प्रयुक्त कर सकें" (बिरूत)।

यदि यूगोस्लाविया स्टालिन काल के 'जनता के जनवादी राज्यों' में राज्य सत्ता में संशोधन विचलन का प्रमुख जीता–जागता सफल उदाहरण है तो यह भी याद रखना चाहिए कि मध्य एवं दक्षिण–पूर्वी यूरोप के दूसरे देशों में भी इसी के समानान्तर दक्षिणपंथी विचलन के चिन्ह प्रकट हो रहे थे।

पोलैण्ड में गोमुलका का प्रमुख दक्षिणपंथी विचलन, जो समाजवाद की ओर निर्बाध संक्रमण को रोक रहा था, जिसने परिस्थितिवश मजबूरन मध्यम पूंजीपतियों और पूंजीवादी किसानों के विरूद्ध रूख अपना रखा था। पोलैण्ड के पश्चिमी हिस्से में गोमुलका और उसके गुट ने, मार्क्सवाद के विपरीत, बड़े कुलक फार्म स्थापित किए और गांवों में पार्टी संगठन के अन्दर गरीब किसान की भूमिका सीमित कर दी। यूगोस्लाविया के विकास ने

गोमुलका गुट को ग्रामीण क्षेत्र में कुलकों के हित साधने की नीति को प्रोत्साहित किया और इसने देहातों में समाजवाद में संक्रमण को टालने का कार्य किया। गोमुलका गुट का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य कोमिन्फार्म (कम्युनिस्ट इनफार्मेशन ब्यूरो) की स्थापना के प्रति उसकी आक्रमकता में भी प्रतिबिम्बित हुआ। इसी प्रकार यूगोस्लाविया में विकास की समझ में भी यह प्रदर्शित हुआ।

पोलैण्ड की पार्टी के मार्क्सवादी–लेनिनवादी घड़े का नेतृत्व बेरूत के हाथों में था। उन्होंने इस दृष्टीकोण का खण्डन किया कि पोलैण्ड की "जनता की जनवादी" व्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक 'लयपूर्ण सुलह–समझौते' को अभिव्यक्त कर रही है। बेरूत का कथन था कि 'जनता की जनवादी' व्यवस्था दो भिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं (समाजवाद और पूंजीवाद) का संश्लेशण था। यह मजबूती से एक–दूसरे के साथ सह–अस्तित्व न होकर, उल्टे पूंजीवादी तत्वों को क्रमशः धक्का देते हुए, दूरगामी तौर पर उसको क्रमशः विनष्ट करना है और साथ ही यह विकास का एक रूप है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास के आधार को मजबूत किया जाना है।" 1949 में अस्थाई तौर पर गोमुलका–स्पाईचेलेस्की गुट को हरा दिया गया। इसने अवशिष्ट पूंजीवादी तत्वों के विरूद्ध समाजवादी निर्माण के काम को जारी रखने की परिस्थिति बनाई एवं जनता के दिमागों में बुर्जुआ विचारधारा की बची हुई ठोस अभिव्यक्तियों के खिलाफ संघर्ष को धार दी। 1953 की पहली अप्रैल तक वहां 7,000 सहकारी कृषि उत्पादक समितियां निर्मित हो गई थीं जिसमें 1,46,500 घर शामिल थे। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस एवं बेरूत की मृत्यु के पश्चात गोमुलका सत्ता में आया। फिर पोलैण्ड में सहाकरी खेती का कार्य कभी भी पूरा नहीं किया जा सका। किसान बुर्जुआजी को सावधानी के साथ सुरक्षित रखा गया, जिसकी वजह से पोलैण्ड कभी भी समाजवादी समाज में संक्रमण के योग्य नहीं हो सका।[22]

इसी प्रकार, रूमानिया में वैसाइल लूका द्वारा दक्षिणपंथी विचलनों के द्वारा समाजवादी बुनियाद को भोंथरा करने की भूमिका निभाई गई, जिसका साथ अन्ना पाकर एवं अन्यों द्वारा समझौतावादी रूख अपनाकर दिया गया। लूका की नीतियों, गोमुलका की ही तरह, टीटो और कार्डलेन की प्रतिध्वनियां थी। उन्होंने उद्योगों के विकास का विरोध किया जो उत्पादन के साधनों को पैदा करते, जिसके कारण समाजवादी औद्योगीकरण की रफ्तार धीमी हो गई; राजकीय फार्मों एवं सामूहिक फार्मों की सक्रियता में अवरोध पैदा किया गया, जिससे खेतों की सामूहिक जुताई के लिए बने संयुक्त किसान समूह हतोत्साहित हुए; तथा खुले बाजार में मूल्य के आधार पर ठेकेदारी एवं खरीद द्वारा मूल्य निर्धारण करने के द्वारा पूंजीवादी वायदा व्यापार को बढ़ावा दिया गया। अन्ना पाकर पर आरोप लगा कि उन्होंने सामूहिक फार्मों के निर्माण की अवहेलना की, समाजवादी कृषि के विकास में कुलकों की कार्यवाहियों की उपेक्षा की और मशीन ट्रेक्टर स्टेशनों की स्थापना के प्रति भारी उदासीनता प्रदर्शित की।

रूमानिया में कुलकों को मजबूत बनाने में कृषि प्रश्न पर दक्षिणपंथी झुकाव एक रोचक तथ्य रहा है। उनमें से अधिकांश को मध्यम किसान के रूप में वर्गीकृत किया गया और इस प्रकार राज्य की टैक्स नीति एवं राजकीय देयों से मुक्त रखने में उनकी मदद की गई। यद्यपि कुलकों के पास अनुमानित 6 से 10 प्रतिशत भूमि थी, किन्तु उनमें से मात्र 2.5 प्रतिशत को उस वर्ग में रखा गया।[23] दक्षिणपंथी विचलन के भण्डाफोड़ एवं उसकी पराजय ने रूमानिया में 'जनता के जनवाद' की प्रथम अवस्था से उसे उसकी दूसरी अवस्था की ओर बाधारहित ढंग से संक्रमण सुनिश्चित किया, जिससे समाजवादी निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना सम्भव हुआ। ख्रुश्चेव के आगमन ने अधिकांश 'जनता के जनवादी' राज्यों में और साथ ही रूमानिया में इस पूरी प्रक्रिया को मन्द करने के साथ उसे उल्टी दिशा में मोड़ दिया।

IV

> "चीन में सर्वहारा एवं किसानों का जनवादी अधिनायकत्व अस्तित्व मे है, कुछ उसी से मिलती–जुलती जो बोल्शेविक 1904–05 में बात किया करते थे।" (स्टालिन, 1950)

22 फरवरी 1952 को सोवियत अर्थशास्त्रियों के साथ अपनी बातचीत के दरम्यान स्टालिन ने पोलैण्ड का उदाहरण देते हुए, मध्य एवं दक्षिण–पूर्वी यूरोपा की जनता की जनवादी संरचनाओं में तथा एशिया की चीन जैसी संरचनाओ में स्पष्ट विभेद किया था। उन्होंने कहा कि यूरोप की जनता की जनवादी संरचनाओं में राजनैतिक सत्ता सर्वहारा के हाथ में है, कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, जिनमें कम्युनिस्टों और मेहनतकशों की भूमिका नेतृत्वकारी है और समाजवाद का निर्माण शहरों में ही न होकर गांवों में भी हो रहा है। चीन में सर्वहारा के अधिनयाकत्व अस्तित्व में नहीं है। इसके स्थान पर वहां सर्वहारा और किसानों का जनवादी अधिनायकत्व है। वहां उद्योगों का राष्ट्रीयकरण पूरा नहीं हुआ है और वहां कम्युनिस्टों और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के बीच खेमा (ब्लॉक) है। चीनी क्रान्ति की विशिष्ट विशेषता यह है कि राज्य के शीर्ष पर कम्युनिस्ट पार्टी है। स्टालिन के विचार से चीन में जनता का जनवादी गणतंत्र है जो अभी जनता के जनवादी राज्य के पहले चरण से गुजर रहा है।[24] उन्होंने यही उदारहण कोरिया एवं वियतनाम तक भी विश्लेषित किया।

स्टालिन की उक्त टिप्पणी के अनुरूप, जो उन्होंने सोवियत अर्थशास्त्रियों के बीच की थी, माओ ने अपनी रचना "जनता का जनवादी अधिनायकत्व" में तर्क दिया कि चीन में राज्य सत्ता 'जनता का जनवादी अधिनायकत्व' है, जिसकी धार साम्राज्यवाद

के खिलाफ है, साथ ही यह सामन्तवाद और उसके स्थानीय लगुआ–भगुआ, अर्थात भूस्वामी वर्ग और नौकरशाही पूंजी, अथवा एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग के भी विरूद्ध है, जिसको उखाड़ फेंकन अभी शेष है।[25] चीन में राज्य सत्ता की बुनियाद मजदूरों और किसानों के गठजोड़ से निर्मित हुई है। जैसा कि माओ ने कहा था कि "जनता कौन"? चीन के वर्तमान चरण में जनता मजदूर वर्ग, किसान, निम्न पूंजीपति वर्ग एवं राष्ट्रीय बुर्जुआ है।"[26] यह उसी तरफ संकेत करता है जिसे स्टालिन "सर्वहारा और किसानों का अधिनायकत्व" कहते हैं। और जिसे 'जनता के जनवादी राज्य' के प्रथम चरण, जो अभी साम्राज्यवाद, सामन्तवाद विरोधी है, से दूसरे चरण, अर्थात समाजवाद की ओर संक्रमण करना है। माओ का इस विषय पर क्या कहना है? यह एक विवा. दास्पद प्रश्न है, जैसा कि यूगोस्लाविया के मसले में जोर देकर स्पष्ट किया गया था। माओ कम्युनिस्ट इनफार्मेशन ब्यूरो के 1948 के प्रथम प्रस्ताव तथा नवम्बर 1949 के द्वितीय प्रस्ताव के मध्य जुलाई 1949 में यह लिख रहे थे। यहां माओ 'सर्वहारा और किसानों के अधिनायकत्व' से 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' में तेजी से और निर्बाध रूप से संक्रमण की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। शायद, बिना किसी संदेह के उचित कार्यनीतिक कारणों से सत्ता में आने के तीन माह पूर्व निश्चित प्राय राजनैतिक अनिवार्यतावश यह उद्देश्य अभिव्यक्त करते हैं जो भविष्य में चीन में सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय बुर्जुआ का एवं इसकी राजनैतिक पार्टियों का राज्य सत्ता से निष्कासन। यही वह क्षण था जब कि एड़ी–चोटी तक का सारा जोर लगाना था, जबकि एकाधिकारी पूंजीपतियों के प्रभाव से, जो च्यांग काई शेक के इर्द–गिर्द केन्द्रित थी, मध्यम पूंजीपतियों के हिस्से को हमें अपने प्रभाव में लाना था, उन्हें जीतना था। स्टालिन द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को दी गई मुख्य सलाहों में यह एक प्रधान सलाह थी जिसका प्रारम्भिक उद्देश्य था कि ऐसे राज्य की स्थापना जिसमें राष्ट्रीय बुर्जुआ के किसी भी हिस्से को राज्य सत्ता में किसी भी रूप में भागीदारी न करने दी जाए।

राष्ट्रीय बुर्जुआ के बारे में माओ इस बात की परम आवश्यकता समझते थे कि समाजवाद की स्थापना के पूर्व, जो उनके विलोपन से कार्यसिद्ध होगा, और उनके प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात दोनों ही स्थितियों में इस वर्ग को शिक्षित किया जाए और सुधारा जाए। उनका तर्क था कि एक बार 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' का कार्यभार पूरा हो जाए

> "तब मात्र राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ही बच जाएगा। वर्तमान चरण में उनके बीच बड़े पैमाने पर उपयुक्त प्रशिक्षण कार्य किया जा सकता है। और जब समाजवाद को सम्भव कर सकने, अर्थात निजी प्रतिष्ठाना के राष्ट्रीयकरण का समय आएगा तब हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, जिससे वे शिक्षित होकर सुधर सकें। जनता के हाथ में एक मजबूत राज्य सत्ता का उपकरण है और उन्हें राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के विद्रोही होने का कोई भय नहीं है।"[27]

यह वाक्यांश भारी जिज्ञासा पैदा करता है क्योंकि 1954 के पश्चात यह दावा कि समाजवाद मे राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के निजी प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, इसे अगले संस्करणों के पाठ से हटा दिया गया। न तो कभी भी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को हटाया गया, न ही चीनी लोक गणराज्य की अर्थव्यवस्था में उनका आर्थिक रूप से सफाया गया गया।

जनवरी 1950 में 'पीपुल्स चाइना' में प्रकाशित यू हुआई के लेख 'चीनी क्रान्ति में राष्ट्रीय बुर्जुआ' में लेखक का तर्क माओ की लाइन के अनुरूप था कि राष्ट्रीय बुर्जुआ को जनता के जनवाद की प्रथम अवस्था में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया कि :

> "स्वाभाविक है, यह कथ्य नहीं है कि अन्तर्विरोध नहीं रह गए हैं, और इसके फलस्वरूप वह संघर्ष भी नहीं रह गया है जो समाजवादी चरित्र के राज्य के स्वामित्व की अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी चरित्र की निजी स्वामित्व के बीच हैं। बिल्कुल नहीं, अन्तर्विरोध मौजूद हैं, अतः संघर्ष भी अवश्यम्भावी है और इन्हें आगे और भी धारदार होना है।

लेकिन चूंकि चीन में विभिन्न वर्गों के बीच आपेक्षिक शक्ति संतुलन में भयंकर परिवर्तन आ चुका है और चूंकि शक्तिशाली राज्य सत्ता का उपकरण अब जनता के हाथ में है, और चूंकि राज्य अर्थव्यवस्था निरंतर संवृद्धि पर है जिसका चरित्र समाजवादी है, जिसके साथ अर्द्ध–समाजवादी चरित्र की सहकारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, जिसकी चीनी अर्थव्यवस्था में नेतृत्वकारी भूमिका है, अतः इस तरह के अन्तर्विरोध एवं संघर्ष के समाधान हेतु अतिरिक्त खून बहाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे प्रशिक्षण और सुध ाार द्वारा काफी हद तक हल किया जा सकता है।[28]

जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समकालीन नेतृत्व के लेखन में शीघ्र एवं निर्बाध संक्रमण, जिसे 'सर्वहारा और किसानों के अधिनायकत्व' से 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' की ओर होना था और उसके कार्यभार को सम्पन्न करने थे, के उल्लेख को जानबूझकर दांवपेच के तहत विलुप्त कर दिया गया था। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) और कोमिन्फर्म को इस तरह की छूट देने की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही कारण। दोनों नि. रंतर स्टालिन और सीपीएसयू(बी) के इस अवस्थान टिके रहे कि चीन की 'जनता के जनवादी अधिनायकत्व' को अभी भी 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' के कार्यभार सम्पन्न करने हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, चीनी क्रान्ति की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर

कोमिन्फर्म की पत्रिका ने लिखा :

> "चीन की राज्य सत्ता 'सर्वहारा का अधिनायकत्व' नहीं है, और इस मसले में यूरोपीय देशों के 'जनता के जनवादी' राज्यों से भिन्न है जहां यह जनवाद 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' के कार्यभारों को सम्पन्न कर रहा है।"
>
> चीन की राज्य सत्ता के 'जनता के जनवादी राज्य' की प्रकृति, इसके अभी भी उपनिवेशिक देश की अवस्थाओं से परिभाषित होती है। वर्तमान में चीन की मेहनतकश जनता समाजवाद के निर्माण के कार्यभार की चुनौती से रूबरू नहीं है, जिसका मुख्य उपकरण 'सर्वहारा का अधिनायकत्व' ही है।"[29]

जनता की जनवादी क्रान्ति में 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' और समाजवाद में बाधारहित संक्रमण का प्रश्न तभी वस्तुगत हो सकता है जब कि युद्ध पूर्व के उत्पादन स्तर हासिल हो जाए और साम्राज्यवाद–सामन्तवाद विरोधी कार्यभार में सफलताएं हासिल की जा सकें।

साम्राज्यवादी स्वार्थों और चीनी दलाल–नौकरशाही बुर्जुआ, जिसके विदेशी साम्राज्यवादियों के साथ घनिष्ठ सम्बंध हैं, के राष्ट्रीयकरण का काम पूरा हो चुका है और राज्य ने उनकी फैक्ट्रियां, मिल, बैंक और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान जब्त कर लिए हैं। कृषि क्रान्ति को पूरा करने के काम, जो इस सिद्धान्त के आधार पर सम्पन्न किया जाना था कि जोतने वाले को जमीन दो, ने भूस्वामी वर्ग के आर्थिक आधार को नष्ट कर दिया है। उस भूस्वामी वर्ग को समाप्त कर दिया गया है और किसान को भूस्वामी वर्ग को दिए जाने वाले वार्षिक कर से मुक्त कर दिया गया है। इस सबका मतलब यह है कि 1952 तक क्रान्ति का सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी कार्यभार मोटामोटी हासिल हो चुका है। और अब चीन का लोक गणराज्य 'सर्वहारा का अधिनायकत्व' स्थापित करने के मुहाने पर खड़ा है, ताकि समाजवाद की दिशा में निर्बाध संक्रमण कर सके।

ऐसी परिस्थितियों में, '6 जून 1952' में माओ कहते हैं कि चीन का प्रधान अन्तर्विरोध राष्ट्रीय बुर्जुआ और मेहतनकश वर्ग के बीच हो गया है।

> भूस्वामी वर्ग एवं नौकरशाही पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने के पश्चात राष्ट्रीय बुर्जुआ और मजदूर वर्ग के बीच अन्तर्विरोध चीन का प्रधान अन्तर्विरोध बन चुका है। अतः राष्ट्रीय बुर्जुआ को अब मध्यवर्ती वर्ग के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए।[30]

उक्त कथन से यही आशय निकलता है कि पीपुल्स चाइना अब 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' के कार्यभार हाथ में लेने की मुद्रा में है और समाजवादी संक्रमण की प्रक्रिया को आरम्भ करेगा।

> ए.आई. सोवोलोव ने इस संज्ञान की पुष्टि की थी :
>
> "जबकि कोरिया का जनता का जनवादी गणराज्य तथा वियतनाम का जनवादी गणराज्य जनता के जनवादी राज्य की ओर विकसित होने की दिशा में प्रथम चरण पर खड़ा है, वहीं चीनी लोक गणराज्य इस प्रथम अवस्था को, जो जनवादी क्रान्ति का चरण था, पहले ही पार कर चुका है। और अब पहले चरण के बाद एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जो समाजवादी क्रान्ति के कार्यभारों को ग्रहण कर रहा है। इन राज्यों की लोकप्रिय जनवादी सत्ताएं एक क्रान्तिकारी शक्ति हैं जो कि किसानों एवं सर्वहारा के अधिनायकतव के कार्यभार को पूरा कर रही हैं।
>
> आगे वे चीन के बारे में कहते हैं :
>
> साम्राज्यवाद–सामन्तवाद विरोधी कार्यभार को सफलतापूर्वक सम्पन्न होने से यह सुनिश्चित हो गया है कि सामान्य जनवादी क्रान्ति सीधे समाजवादी क्रान्ति की दिशा पकड़ेगी। आज चीन की जनता मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, जिसके शीर्ष पर उसकी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी है, ने अप. ने आपको समाजवादी क्रान्ति के कार्यभार को हाथ में लेने को तैयार कर लिया है, जिससे समाज का समाजवादी रूपांतरण सम्भव हो सके।[31]

उक्त वक्तव्य में स्पष्टता से यह समाहित है कि चीन में किसानों एवं सर्वहारा कोअधिनायकत्व को सर्वहारा अधिनायकत्व में बदलना अनिवार्य है ताकि समाजवाद में संक्रमण सम्भव हो सके।

V

"पूंजीवादी समाज से समाजवादी समाज में संक्रमण के दरम्यान एक का दूसरे में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने के बीच एक कालखण्ड होता है। इसके घटित होने के साथ ही राजनैतिक संक्रमण का भी एक दौर रहता है, जिसमें राज्य और कुछ नहीं हो सकता है, सिवाय इसके कि सर्वहारा का क्रान्तिकारी अधिनायकत्व स्थापित रहे।" मार्क्स

मार्च 1953 के बाद सोवियत राज्य ने सर्वहारा के अधिनायकत्व के कार्यभार को पूरा करना बन्द कर दिया। सर्वहारा के अधिनायकत्व, जो समाजवाद को कायम रखने और साम्यवाद की ओर निर्बाध संक्रमण की बुनियादी जरूरत है, के परित्याग को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1961 में यह घोषित करते हुए औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया कि अब सोवियत राज्य को आधिकारिक तौर पर 'सम्पूर्ण जनता का राज्य' माना जाएगा।

1953 से 1958 के बीच यूएसएसआर में सामान्य उत्पादनों की एक व्यवस्था बनाई गई। केन्द्रीय योजना गौसप्लान के निदेशक ने साम्यवादी निर्माण योजना को निरस्त कर दिया और इसे एक नई व्यवस्था, संघीय गणतंत्र और केन्द्रीय सरकार के राजकीय कार्यालयों की 'समन्वित योजना' में तब्दील कर दिया गया। गौसप्लान का स्वयं भी पुनर्गठन किया गया और इसे दो संगठनों में विभाजित कर दिया गया। गौसप्लान की कीमत पर प्रतिष्ठानों के निदेशकों की शक्ति को बढ़ाया गया और उनसे यह मांग की गई कि प्रतिष्ठानों के संचालन में *योग्यता का पैमाना* 'लाभ के सिद्धान्त' का पालन करें। कृषि में उत्पादन के साध ानों एवं औजारों को —— मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों को सामूहिक फार्मों को बेच दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि उत्पादन के साध ानों का एक हिस्सा, जो समाजवादी सम्पत्ति थी, सामूहिक फार्मों के छोटे समूह को हस्तान्तरित कर दी गई और इस प्रकार वह उपभोग मालों के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। समाजवाद के अन्तर्गत सोवियत उद्योगों का उत्पादन योजना के मुताबिक आवंटित किया जाता था। 1958 के बाद सोवियत उद्योगों के उत्पादन को राजकीय क्षेत्रों में परिचालित होने वाली मालों के रूप में नए तरीके से चिन्हित किया गया। और सोवियत उद्योगों के उत्पादन की बिक्री हेतु गौसप्लान के अन्तर्गत एजेन्सियां बनाकर स्थापित किया गया। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक वर्गीकरण, जैसे कि मजदूरी, अतिरिक्त मूल्य, मुनाफा, औसत मुनाफा, पुनः प्रकट हो गए।32

सोवियत संघ में सर्वहारा के अधिनायकत्व के खात्मे और पूंजीवाद के निर्माण के परिणाम जनता के जनवादी व्यवस्था वाले देशों के लिए बहुत व्यापक हुए।

टप्

"समाजवाद को प्राप्त करने के मार्ग पर मात्र सीधे बढ़ते जानेसे 'जनता के जनवादी' राज्य अपने आपको स्थित और सबल बना सकते हैं और अपनी ऐतिहासिक मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये शोषक वर्गों के खिलाफ संघर्ष रोक देते हैं, उनको खत्म करने का काम बन्द कर देते हैं तो शोषक वर्ग अनिवार्य रूप से हावी हो जाते हैं और वे जनता के जनवादी राज्य को खत्म करने के करीब पहुंच जाते हैं।" दिमित्रोव

मध्य और दक्षिण—पूर्वी यूरोप में जनता के जनवादी राज्य, जैसा कि हम देखते हैं, 1947—48 से सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित करते हैं और समाजवादी निर्माण के पथ पर अग्रसर होना शुरू करते हैं। जबकि एशिया की जनता की जनवादी संरचनाएं अभी अप नी प्राथमिक चरण में हैं, जिसे हम सर्वहारा और किसानों के अधिनयाकत्व की अवस्था कहते हैं। और चीन एकदम इस मुहाने पर खड़ा है कि वह निर्बाध रूप से समाजवादी संक्रमण की ओर आगे बढ़े, जिसके लिए एकमात्र शर्त है कि वह सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित करे।

20 सितम्बर 1954 को जब चीन ने अपना संविधान स्वीकार किया, वह एक अवसर था कि जहां से वह सर्वहारा के अधिनायकत्व के निर्माण को दर्ज कर सकता था। उन्होंने 'चीनी लोक गणराज्य के संविधान के दस्तावेज' पर 14 जून 1954 के दिन अपने भाषण में जोर देकर कहा कि 'सर्वहारा के अधिकनायकत्व' की लेनिनवादी समझ किसी भी रूप में अप्रासंगिक या पुरानी नहीं पड़ गई है। बल्कि उन्होंने 1954 के चीनी संविधान को समाजवादी प्रकार का वर्णित किया।[33] माओ ने सूचित किया कि चीनी संविधान के दस्तावेज को सोवियत संघ एवं 'जनता के जनवादी राज्यों' के संविधान से ग्रहण करके ही बनाया गया है।[34] किन्तु माओ इस मार्क्सवादी—लेनिनवादी समझ को स्वीकार नहीं करते कि समाजवाद में संक्रमण हेतु सर्वहारा का अधिनायकत्व आवश्यक पूर्व—शर्त है। स्टालिन, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) तथा कम्युनिस्ट एवं वर्कर्स पार्टियों के सूचना ब्यूरो ने अविलम्ब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समक्ष यह प्रश्न रखा। 1954 के चीनी संविधान मे चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में विभिन्न जनवादी पार्टियों को शामिल करने से लेकर शायद वर्तमान तक के जारी सभी संविधानों द्व ारा यह बात निश्चित होती है कि चीनी लोक गणराज्य में सर्वहारा के अधिनायकत्व के कार्यभार कभी भी सम्पन्न नहीं किए गए। वस्तुतः सच्चाई यह है कि 1949 में गठित सर्वहारा एवं किसानों का अधिनायकत्व , जिसमें राष्ट्रीय बुर्जुआ शामिल था, यह संरचना ही पूरे माओ काल एवं उसके पश्चात तक वैसे ही स्थाई रूप से अस्तित्वमान रही। अपनी एक मौलिक रचना "जनता के बीच अन्तर्विरोधों को सही ढंग से हल करने के बारे में", जिसे माओ ने 27 फरवरी 1957 में लिखा था, उन्होंने अपने तर्कों को और आगे विकसित किया। उन्होंने व्याख्या की कि राष्ट्रीय बुर्जुआ देश की ठोस परिस्थितियों में समाजवाद हेतु कार्य कर रहा है और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में मजदूर वर्ग की राजनैतिक पार्टियां और राष्ट्रीय बुर्जुआ की पार्टियां लम्बे समय तक सह—अस्तित्व में तथा एक—दूसरे की देखरेख में काम करेंगी। अपने काम करने के दरम्यान उद्योगपति एवं व्यापारी अपने आपको परिवर्तित करेंगे।[35] स्पष्ट ही है कि पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के दरम्यान 'वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है' की लेनिनवादी समझ को माओ स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यह लेनिनवादी समझ कि बुर्जुआजी के खिलाफ संघर्ष में सर्वहारा का अधिनायकत्व आवश्यक है क्योंकि 'लघु पैमाने पर उत्पादन अभी संसार में व्यापक तौर पर जारी है और लघु पैमाने पर उत्पादन पूंजीवाद को और बुर्जुआजी को प्रति क्षण, प्रतिघण्टे और प्रतिदिन निरंतरता के साथ बड़े पैमाने पर पैदा करता रहता है। ये ही वे कारण है जिनकी वजह से सर्वहारा का अधिनायकत्व अति आवश्यक है। दूरगामी, भीषण संकल्प, जीवन—मृत्यु के संघर्ष, जो दृढ़ता के साथ जूझने की मांग करता

है, के बिना बुर्जुआजी के ऊपर विजय प्राप्त करना असम्भव है। बुर्जुआजी पर विजय प्राप्त करनी है, इसकी एकमात्र दृढ़ इच्छा–शक्ति, प्रतिबद्धता और अनुशासन ही इसे सम्भव बना सकती है। (वामपंथी कम्युनिज्म, एक बचकाना मर्ज) किन्तु माओ कुछ ऐसा समझ रहे थे कि चीन में समाजवाद के निर्माण में बुर्जुआ वर्ग मदद करेगा, यह सम्भव है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने अवस्थानों को कैसे और मजबूत करती है और मार्क्सवाद–लेनिनवाद को सर्वहारा की अधिनायकत्व की आवश्यकता पर कैसे समझ सुनिश्चित करती है? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) और कोमिन्फर्म द्वारा 1949 से 1953 के बीच खुले तौर पर यह सार्वजनिक अवस्थान अपनाए जाने के अनुसार कि चीन में सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना करने का काम अभी शेष है, और यह एक ऐसा विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ऐसा दावा करके इसको सामान्यतया हल कर दिया जाता है कि 1949 में सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो चुका है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उसका तर्क यह बताती है :

> चीनी लोक गणराज्य की स्थापना के बाद एक जनता के जनवादी अधिनायकत्व की स्थापना हो गई है, जिसका नेतृत्व मजदूर वर्ग मजदूर–किसान संश्रय के आधार पर कर रहा है। वस्तुतः तत्व में यह राज्यसत्ता सर्वहारा अधिनायकत्व का एक रूप है। हमारे देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों में इसने अपने संश्रय में न केवल किसानों और पेट्टी बुर्जुआ (निम्न पूंजीपति वर्ग) को ही शामिल किया है, बल्कि उस राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग को भी अपने साथ रखा है जिसने मजदूर वर्ग के नेतृत्व को सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है।[36]

अनिवार्यतः मजदूरों एवं किसानों के जनवादी अधिनायकत्व की स्थापना 1949 में होने के बाद स्थिर रूप ग्रहण करती गई और सर्वहारा के अधिनायकत्व के कार्यभार पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकी। इसकी तार्किक निष्पत्ति के रूप में चीन का यह दावा कि वे समाजवादी संक्रमण की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, सही नहीं ठहर सकता है। यह सुस्पष्ट है क्योंकि चीन में समाजवादी आर्थिक संबंध आगे नहीं बढ़ सके।

चीनी लोक गणराज्य में राष्ट्रीय बुर्जुआ को आर्थिक रूप से समाप्त नहीं किया गया। 1949 में वे औद्योगिक प्रतिष्ठान जो राष्ट्रीय पूंजी द्वारा संचालित थे 1,23,165 थे, जिनमें 16,40,000 श्रमिक कार्यरत थे। 1950 में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या, जिनमें निजी दुकानदार भी थे, 40,20,000 थी, जिनमें 66,62,000 लोग काम करते थे।[37] समाजवादी संक्रमण के दरम्यान राष्ट्रीय बुर्जुआ को राज्य–व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों के रूप में गठित करके शुरू में नियंत्रित किया गया, जिसे चीनी राज्य द्वारा 5 प्रतिशत लाभ की गारंटी दी गई। जैसे–जैसे उत्पादन में वृद्धि हुई, वैसे–वैसे राज्य के सापेक्ष राष्ट्रीय बुर्जुआ के लाभ की दर में समानुपातिक कमी होती गई। साथ ही, श्रम की उत्पादकता बढ़ते जाने से राष्ट्रीय बुर्जुआ की बोनस और लाभांश के रूप में पूंजी वृद्धि हुई। अतः पूंजी पर उनके लाभ दर का अनुपात बढ़ता गया।[38] इस समय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय बुर्जुआ की पकड़ सोचनीय तरीके से बढ़ गई। 1956 के पूर्वार्द्ध में राजकीय पूंजीवादी क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन सकल उत्पादन का 32 प्रतिशत ठहरता था और चीन के खुदरा व्यापार में वाणिज्य में इसका हिस्सा 25.24 प्रतिशत था।[39]

चीन में यह 'राजकीय पूंजीवाद' की नीति की प्रेरणा उस नई आर्थिक नीति (एनईपी) से मिली थी जिसे सोवियत संघ को बाध्य होकर पूंजीवादी दिशा की ओर लौटना और समझौता करना पड़ा था क्योंकि 'युद्ध साम्यवाद' के अन्त में समाजवाद को धक्का लगा था। जबकि इसके ठीक विपरीत, चीनी लोक गणराज्य इस नीति को तब लागू कर रहा था जब चीन में जनता के जनवादी राज्य का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका था और वह जाहिरा तौर पर समाजवादी संक्रमण की दिशा में कदम आगे बढ़ रहा था।

सांस्कृतिक क्रान्ति के वर्षों में राष्ट्रीय बुर्जुआ को आगे और नियंत्रित किया गया। उनकी पूंजी पर ब्याज को आगामी 12 वर्षों तक स्थगित कर दिया गया। माओ पुनः 1949 के अपने उस वक्तव्य पर वापस लौट आए कि राष्ट्रीय बुर्जुआ और उनके प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण होना है। यह दिमित्रोव की समझ के अनुरूप था कि अगर जनता की जनवादी संरचनाओं को समाजवाद के दूसरे चरण की ओर प्रगति करनी है तो शहरी–कस्बाई बुर्जुआजी, जो शोषक वर्ग के अन्तिम अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को समाप्त करना होगा। यह अति आवश्यक इसलिए है कि यदि पूंजीवाद की जड़ों के अवशेष अन्तिम तौर पर नाश नहीं की जाएंगी तो वे पुनः अपने शासन को स्थापित कर लेंगे।40 सांस्कृतिक क्रान्ति के बाद राष्ट्रीय बुर्जुआ की अवरूद्ध पूंजी को, जो उनके बैंकों में जमा थी, पुनः उन्हें वापस दे दिया गया।

चीनी लोक गणराज्य में सर्वहारा के अधिनायकत्व के कार्यभार को पूरा करने में कमी के स्पष्ट फलित थे कि भस्वामी और कुलकों के लिए उनकी हितैषी नीतियों को स्वीकार किया गया। एंगेल्स ने अपनी रचना 'फ्रान्स एवं जर्मनी में किसानों का प्रश्न' में स्पष्ट किया था कि सहकारी समितियों की सदस्यता मात्र छोटे किसानों को ही दी जाएगी और उन्होंने धनी किसानों से समझौते की किसी भी सम्भावना को एकदम से नकार दिया था।[41] सोवियत संघ में मार्क्स और एंगेल्स के विचारों के अनुरूप बुर्जुआजी के सबसे बड़े हिस्से, कुलक को बाहर रखा गया था। सामूहिक फार्मों के अवस्थान के लिए यह अनिवार्यतम था।42

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थायित्व के लिए और भूस्वामीयों

को अलग–थलग करने के लिए माओ ने इस नीति का समर्थन किया कि धनी किसान की सम्पत्ति और अतिरिक्त भूमि को जब्त न किया जाए और हर सम्भव कोशिश की गई कि उनकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रह सके, जैसा कि 1950 के वक्तव्य में परिलक्षित होता है :

> "धनी किसानों के प्रति हमारी नीति को धनी किसानों की अतिरिक्त भूमि और सम्पत्ति को जब्त करने की नीति से धनी किसानों की अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने की नीति में परिवर्तित करना होना चाहिए, जिससे ग्रामीण इलाकों में उत्पादन को और भी जल्द बहाल किया जा सके। यह नीतिगत परिवर्तन भूस्वामियों को भी अलग–थलग करने में मदद करेगा, जबकि यह मध्यम किसानों की सुरक्षा करेगा और छोटे–छोटे भूखण्ड किराये पर लेने वालों की भी रक्षा करेगा।"[43]

मुक्ति के बाद पीपुल्स चीन में स्थापित बुनियादी सामूहिक फार्म गरीब और मध्यम किसानों को लेकर बने थे। 1955 के बाद सामूहिक फार्म में कुलक भी शामिल हो गए। इस प्रकार 1953 के बाद के चीनी सामूहिक फार्मों और 1948 के कोमिन्फॉर्म प्रस्ताव के बाद यूगोस्लाविया में बने सामूहिक फार्मों के बीच एक पारिवारिक समरूपता थी, जिसकी 1949 के कोमिन्फॉर्म प्रस्ताव में आलोचना की गई थी। लेकिन इसके अलाावा चीन में भूतपूर्व भूस्वामियों को सामूहिक फार्मों में लाया गया। कृषि सहयोग के उत्थान के दौरान अधिकांश धनी किसानों और भूतपूर्व भूस्वामियों को सहकारी समितियों में शामिल कर लिया गया।[44] प्रतिक्रियावादी सामाजिक वर्ग, कुलक और भूस्वामियों को बाद में 'जन कम्यूनों' में शामिल किया गया। ये कम्यूनें सोवियत संघ के कम्युनों से भिन्न थे क्योंकि ये मेहतनकश किसानों के अपने वर्गीय घटक के लिहाज से बने थे और जिनमें उत्पादन के औजारों और साधनों का समाजीकरण किया गया था और वे समूह की सम्पत्ति का हिस्सा नहीं थे।

सोवियत संघ में 1953 के बाद ख्रुश्चेव द्वारा अपनाई गई कई सारी आर्थिक नीतियों को पीपुल्स चीन में अपनाया गया। एंगेल्स ने 'एन्टी–ड्युहरिंग' में बताया था कि आर्थिक समुदायों में उपभोग मालों का परिचलन अनिवार्य रूप से पूंजीवाद के पुनरुत्थान के लिए बाध्य था। इस कारण से, स्टालिन ने सानिना और वेन्जहर के इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों में केन्द्रित उत्पादन के बुनियादी उपकरणों को सामूहिक खेतों को बेच दिया जाए।[45] 1958 में सोवियत संघ और पीपुल्स चीन में मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों के बुनियादी कृषि उपकरणों को बेच दिया गया था। ट्रैक्टर स्टेशन सामूहिक फार्मों को बेच दिए गए। परिणामस्वरूप, दोनों राज्यों में उत्पादन के साधनों की एक बड़ी मात्रा अब उपभोग मालों के परिचलन के क्षेत्र का हिस्सा बन गई। 1952 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) की 19वीं कांग्रेस में सामूहिक फार्मों में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) कार्य में संलग्न होने के प्रस्ताव की मैलेन्कोव ने आलोचना की थी क्योंकि यह अकुशल, अपेक्षाकृत महंगा और कृषि से ध्यान हटाने वाला था।[46] ख्रुश्चेव के तहत उपभोक्ता मालों के परिचालन (कमोडिटी सर्कुलेशन) का दायरा काफी बढ़ गया था। सोवियत संघ ने सामूहिक फार्मों में खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए बिजली स्टेशनों और औद्योगिक उद्यमों का काम किया जाने लगा।[47] इसी प्रकार, पीपुल्स चीन में आधुनिक उर्वरक संयंत्रों सहित पीपुल्स कम्यूनों में हजारों ग्रामीण उद्योग स्थापित किए गए। माओ ने बताया कि 'कम्यून में न केवल भूमि और मशीनरी, बल्कि श्रम, बीज और उत्पादन के अन्य साधन भी कम्यून के स्वामित्व में हैं। इसी प्रकार उत्पादन का भी स्वामित्व है।[48] तथ्य यह है कि पीपुल्स कम्यूनों के पास उत्पादन के बुनियादी साधन, भूमि, बुनियादी कृषि मशीनरी का स्वामित्व था, और वे तमाम कम्यून–आधारित उद्योग भी संचालित करते थे, जिसका मतलब था कि उत्पादन साधनों की 'विशाल' मात्रा राज्य सम्पत्ति, जो सम्पूर्ण जनता की सम्पत्ति का गठन करता था, के क्षेत्र से बाहर थे। यह स्पष्ट है कि पीपुल्स चीन में, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अनुपस्थिति में, उपभोग माल उत्पादन और परिचलन का एक विशाल क्षेत्र राज्य–निजी क्षेत्र और जन कम्यूनों में मौजूद था जो समाजवाद के निर्माण के साथ असंगत था।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की इन चीजों के प्रति क्या प्रतिक्रया थी? क्या उन्होंने समाजवाद में संक्रमण के लिए निर्णायक पूर्व–शर्त के रूप में पीपुल्स चीन में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के कार्यों को करने की आवश्यकता की मार्क्सवादी समझ की रक्षा की और क्या इसका विरोध किया कि पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि में बुनियादी नियमों को बदलना सम्भव नहीं है? जैसा कि दिमित्रोव ने कहा था कि यह सभी देशों के लिए वैध था? नहीं, इसके विपरीत, पीपुल्स चीन के राजनैतिक और आर्थिक विकासक्रम पर सोवियत नेतृत्व ने मुहर लगाई, जिसमें यह भी शामिल था कि वे सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के कार्यभार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का समर्थन करने से इनकार कर रहे थे, एवं 1953 के बाद राष्ट्रीय बुर्जुआ और साथ ही धनी किसान–भूस्वामियों के प्रति दक्षिणपंथी दृष्टिकोण अपनाने की नीति पर चल रहे थे। ख्रुश्चेव ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस के अवसर पर यह टिप्पणी की कि चीनी लोक गणराज्य में समाजवादी निर्माण करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, वह अद्भुत और विशिष्ट घटित हो रहा है।

"निर्णायक नेतृत्वकारी अवस्था हासिल करने के पश्चात, जनता का जनवादी राज्य उनका इस्तेमाल सामाजिक क्रानित के लिए कर रहा है, जिससे निजी उद्योगों एवं व्यापार के शान्तिपूर्ण पुनर्गठन

की नीति को लागू किया जा स के और उसका समाजवादी अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के रूप में क्रमशः परिवर्तन किया जा सके।"[48]

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने स्वरूप में विभिन्नताओं के बावजूद, मार्क्सवाद –लेनिनवाद के उस दृष्टिकोण का खण्डन कर रहे थे, जो समाजवाद के निर्माण में 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' के बारे में सुस्थापित था।

VII

> "जनता के जनवाद" की अवधि अपने पूरे दौर में अपने चरित्र को नहीं बदलेगा, अपनी नीतियों को लागू करने के दरम्यान उसका उद्देष्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी तत्वों को निष्कासित करने का बना रहेगा। सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में मजदूर वर्ग की केन्द्रीय हैसियत को निरंतर मजबूत करते रहना है और उन सभी ग्रामीण तत्वों को लामबंद करना है जो कुलकों और उसके लग्गु–भग्गुओं के विरूद्ध तीखे संघर्षों की अवधि में मजदूर वर्ग के संश्रयकारी बन सकते हैं। वर्ग शत्रुओं को शक्तिहीन करने एवं उनका खात्मा करने के लिए जनता के जनवाद को ताकतवर और उन्नत करना अति आवश्यक है।" —— दिमित्रोव

15 अगस्त, 1945 को सोवियत सैनिकों ने जापानी क्वो. मिन्टाग सेना को हराकर कोरिया को जापानी साम्राज्यवाद के 36 साल लम्बे शासन से मुक्त कराया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुक्ति पाने वाला कोरिया पहला उपनिवेश था। इन परिस्थितियों में,

> "मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनता ने प्रतिगामी ताकतों को कुचलकर अपनी स्वयं की सत्ता स्थापित की। जन समितियां, जिसने राज्य सत्ता की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी, पूरे देश में उभरीं। सर्वहारा वर्ग और किसानों के अधिनायकत्व के कार्यभार को पूरा करने के लिए एक क्रान्तिकारी शक्ति वहां मौजूद थी। अपनी सत्ता स्थापित करने के दरम्यान व्यापक जनता ने जनवादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बड़े पैमाने पर हासिल किया। कोरिया में जनता के जनवादीकरण का एक नया युग प्रारम्भ हो गया।[49]

पाक हेन एन ने कमयुनिस्ट पार्टी को पुनर्गठित करने करने का काम हाथ में लिया और वे पार्टी के महासचिव बने। इस उद्देश्य हेतु एक तैयारी समिति को बनाया गया और कार्यवाहियों के कार्यक्रम को तय किया गया। देश में जनवादी शक्तियों का केन्द्र बिन्दु कम्युनिस्ट पार्टी बन गई।[50] 1945 के अक्टूबर में किम इल सुंग कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सांगठनिक ब्यूरो के प्रमुख बने।

नव जनवाद की आवश्यकताओं के अनुरूप, किल इल सुंग ने उस समय तर्क दिया कि कोरिया को इस वक्त प्रगतिशील जनवादी रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जो जनता को अधिकार, स्वतंत्रता और पूर्ण आजादी देगी। प्रगतिशील जनवाद, उन्होंने कहा, पश्चिमी देशों लोकतंत्र और समाजवाद दोनों से भिन्न है; यह नवीन प्रणाली का जनवाद साम्राज्यवाद–सामन्तवाद विरोधी होगा, जो मात्र एक वर्ग के लिए न होकर व्यापक जनता और देशभक्तों के हितों की पूर्ति करेगा। तदनुसार, कोरिया में एक जनवादी राष्ट्रीय मोर्चा बनाया जाना था, जिसमें मजदूरों, किसानों, बुद्धि जीवियों, धार्मिक समुदायों और 'ईमानदार राष्ट्रीय पूंजीपतियों' को —— सभी जनवादी और देशभक्त शक्तियों को शामिल किया गया।[51] वर्गों के इस गठजोड़ ने दोनों, अर्थात, नव जनवाद और जनता के जनवाद के प्रथम चरण की आवश्यकताओं के सापेक्ष सम्बंधित कार्यभारों को हाथ में लिया। इस परिदृश्य में, भूस्वामियों की सम्पत्ति, दलाल पूंजी, जापान समर्थक तत्वों पर राज्य का पूरी तरह कब्जा हो गया। मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया एवं कृषि क्रान्ति का कार्य आगे बढ़ा। इन नीतियों ने उत्तरी कोरियाई समाज के औपनिवेशिक–अर्द्ध सामन्ती चरित्र को समाप्त कर दिया। पूंजीवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कस्बों–शहरों में निजी उद्योग और व्यापार जीवित रहा और देहातों में बुर्जुआजी का बड़ा हिस्सा एवं कुलक अस्तित्व में बने रहे।[52] 19 47 तक वहां उद्योगों में राज्य का नियंत्रण 80.2 प्रतिशत था, शेष 19.8 प्रतिशत निजी क्षेत्र में।[53] 1949 तक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का राजकीय और सहकारी क्षेत्र बढ़कर 90.7 प्रतिशत हो गया। कृषि में समाजवादी क्षेत्र राजकीय फार्मों, पशुधन प्रजनन फार्मों एवं फार्म मशीन लीज स्टेशनों से मिलकर बना था। 1949 में ये सब मिलकर कृषि अनुभाग का 3.2 प्रतिशत हिस्सा थे, जो 1955 में बढ़कर नेतृत्वकारी हैसियत में पहुंच गए। 1056 के अन्त तक कुल कृषक परिवारों के 65.2 प्रतिशत हिस्से को शामिल कर कृषि सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। पहला मशीन ट्रैक्टर स्टेशन सोवियत संघ की सहायता से 1950 में स्थापित किया गया था।

9 सितम्बर 1948 को 'कोरियाई जनता के जनवादी गणतंत्र' की घोषणा की गई थी। हालांकि, 1950 और 1953 के बीच कोरिया पर अमेरिकी आक्रमण ने जनता के जनवाद के पहले चरण से दूसरे चरण के जनवादी अधिनायकत्व में निर्बाध संक्रमण के लिए मामलों को बहुत जटिल बना दिया था। सर्वहारा और किसानों के अधिनायकत्व से सर्वहारा के अधिनायकत्व,, जो कि समाजवाद की ओर संक्रमण का बुनियादी आधार है, के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद के कारण हुई बर्बादी से आर्थिक तौर पर उबरना जरूरी था।

अगस्त 1958 में यह दावा किया गया कि डेमोक्रेटिक

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) में उत्पादन सम्बंधों में, देहात और शहर दोनों में समाजवादी संक्रमण का कार्यभार पूरा कर लिया गया है, इसलिए समाजवाद यहां मजबूती से स्थापित हो चुका है।[55]

किन्तु डीपीआरके में सर्वहारा और किसानों के अधिनायकत्व से सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना नहीं हो पाई। इस काम के लिए यह अनिवार्य था कि डीपीआरके में में अब तक के शासकों को, अर्थात, राष्ट्रीय बुर्जुआ को संयुक्त मोर्चे से पूरी तरह निकाल बाहर फेंका जाता। 1956 की मार्च में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस के तुरन्त बाद के माह में किम इल सुंग ने लिख कर यह दावा किया कि बहरहाल इस जनता की सत्ता ने सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना कर ली है।

कुछ लोगों का यह कथन कि यह जनता की सत्ता वह संरचना नहीं है जिसे सर्वहारा का अधिनायकत्व कहा जा सके क्योंकि यह एक संयुक्त मोर्चे पर आधारित है; यह पूरी तरह से एक गलत दृष्टिकोण है। हमारी जनता की सत्ता एक ऐसी राज्य सत्ता है जो सर्वहारा के अधिनायकत्व के वर्गीकरण में शामिल होने के योग्य है। गणतंत्र के उत्तरी आधे भाग में अब पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के काल में जनता की सत्ता के सर्वहारा के अधिनायकत्व के कार्यभार को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है।[56]

ऐसा कहा गया था कि सर्वहारा के अधिनायकत्व के कार्यभार को समेकित रूप से पूरे करने आवश्यक हैं क्योंकि वहां शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता मालों के लघु वस्तु उत्पादक, निजी निर्माता, निजी व्यापारी मौजूद थे, और समाजवादी क्रान्ति के कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता थी।[57] तब किम इल सुंग ने कैसे यह दावा किया कि डीपीआरके में सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो गया है, जबकि तथ्य यह था कि यह वहां स्थापित नहीं हुई थी और वहां अभी सर्वहारा और किसानों का अधिनायकत्व अस्तित्व में था। इसे यह तर्क देकर किया गया कि संक्रमणकाल और सर्वहारा के अधिनायकत्व के प्रश्नों का निर्णय मार्क्सवाद–लेनिनवादके प्रेक्षण स्थल से निश्चित न करके ज्यूचे सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना था। कोरियाई नेता ने कहा, 'अन्य देशों की सोच' को खारिज करके 'हठधर्मिता' और 'मूर्खतावाद' से बचना जरूरी है। मार्क्स ने विकसित पूंजीवादी देशों के संदर्भ में इन सवालों की जांच की थी और लेनिन ने भी एक पिछड़े, लेकिन फिर भी पूंजीवादी देश में काम किया था। कोरिया में समाजवादी निर्माण के व्यवहारिक अनुभवों से आगे बढ़ना आवश्यक था।[58] इसका सीधा अर्थ यह था किसी भूतपूर्व औपनिवेशिक और अर्द्ध–सामन्ती देश में जनता के जनवाद के लिए राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे से या आर्थिक रूप से निकाल बाहर करना, अथवा कुलकों एवं राष्ट्रीय बुर्जुआ की आर्थिक शक्ति को समाप्त करना अनिवार्य नहीं था। ज्यूचे सिद्धान्त के अनुसार मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन के सिद्धान्त कोरिया पर लागू नहीं होते थे। इसके विपरीत, स्टालिन और कोमिन्फॉर्म बहुत स्पष्ट थे कि भूतपूर्व औपनिवेशिक देशों में पूरब के नव–निर्मित जनता के जनवादों में मार्क्सवादी सिद्धान्त लागू होते थे।

कोरियाई वर्कर्स पार्टी ने अपनी इस समझ को अभिव्यक्त किया था कि एक उपनिवेश में क्रान्ति के सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के पश्चात उसे समाजवाद के संक्रमणकाल से होकर गुजरना होगा। जनता के लिए यह कार्य आवश्यक है जिसे वे मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनता के जनवादी राज्य के द्वारा विदेशी और घरेलू साम्राज्यवादी शक्तियों और सामन्ती भूस्वामियों को समाप्त कर, महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर और स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद डालकर सम्पन्न करेंगे। वे यह सारा कार्यभार तैयारी की अवधि में करेंगे जिसे जनता की जनवादी क्रान्ति के नाम से जाना जाता है। इस जनता के जनवादी अधिनायकत्व का नेतृत्व मजदूर वर्ग के हाथ में होगा जो मजदूर–किसान संश्रय पर आधारित होगा और जिसके साथ राष्ट्रीय बुर्जुआ भी गठजोड़ में शामिल होगा।[59] यहां तक तो ठीक है, किन्तु बाद में यह सोच लिया गया कि जनता का जनवादी अधिनायकत्व वस्तुतः सर्वहारा का अधिनायकत्व के कार्यभार को ही सम्पन्न करती है। यह तर्क उस भेद को ही मिटा देता है जो सर्वहारा के अधिनायकत्व और जनता के जनवादी अधिनायकत्व के बीच होता है। यह तर्क जनता के जनवाद के दो चरणों के बीच, जनता के जनवाद के दो चरणों के वर्गीय आधारों के बीच और जनता की जनवादी क्रान्ति कि दो चरणों के विशिष्ट कार्यों के बीच भेद को समाप्त कर देता है। कुल मिलाकर इसका परिणाम राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और ग्रामीण पूंजीपति वर्ग की आर्थिक शक्ति को ध्वस्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए उत्तरी कोरिया में सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित नहीं करने को उचित ठहराना था। इनका उन्मूलन करने के स्थान पर इन प्रतिगामी बुर्जुआ वर्गों 'शिक्षित किया गया और उन्हें समाजवादी कामगार जनता में बदला गया।' आगे चलकर यह दावा भी किया गया कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीवादी स्वामित्व का 'पूरी तरह से उन्मूलन' कर दिया गया है।[60]

राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग व्यापारी और विनिर्माण उद्योगों के तत्वों से बना था। 1949 में राजकीय क्षेत्र तथा सहकारी औद्योगिक प्रतिष्ठनों का कुल मिला–जुला उत्पादन 90.7 प्रतिशत बनता था जो 1955 से शुरू हुई समाजीकरण की प्रक्रिया के बाद 98.3 प्रतिशत हो गया था।

हस्तशिल्प के पुनर्गठन के साथ निकट संयोजन में व्यावसायिक लाइनों के अनुसार उत्पादकों की सहकारी समितियों

को संगठित कर पूंजीवादी व्यापार और उद्योग को रूपांतरित किया गया। उत्पादक सहकारी समितियों के तीन रूप थे। पहला रूप सहाकरी अर्थव्यवस्था का प्रारम्भिक रूप था, जिसमें उत्पादन के उपकरणों को साझे स्वामित्व के अन्तर्गत नहीं रखा गया था और केवल काम को सामूहिक आधार पर किया जाता था। दूसरा अर्द्ध–समाजवादी रूप था, जिसमें उत्पादन के साधन साझा और निजी स्वामित्व दोनों के अधीन थे तथा किए गए काम के अनुसार समाजवादी वितरण और निवेश की मात्रा अनुसार वितरण दोनों ही लागू थे। तीसरा रूप पूर्णतया समाजवादी रूप था जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों एवं कोष को सामूहिक सम्पत्ति में दिया गया था और केवल समाजवादी वितरण लागू किया गया था। पूंजीवादी व्यापार और उद्योग में अमूमन दूसरा रूप ज्यादा लोकप्रिय था। यह एक तर्कसंगत रूप था जो पूंजीपतियों को सहज ही स्वीकार्य था क्योंकि इसमें वितरण के तरीके का आधार लागत की मात्रा थी, जबकि उत्पादन के साधनों और वितरण में स्वामित्व पर समाजवादी सिद्धान्त लागू करने पर जोर दिया गया था। उद्यमों की एक अच्छी–खासी संख्या इस दूसरे रूप के माध्यम से तीसरे रूप की ओर चले गए थे।

सोवियत संघ में निजी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण के आधार पर समाजीकरण किया गया था जो समपत्ति सारी जनता की सम्पत्ति बन गई थी। इसके अलावा, सोवियत संघ में सामूहिक फार्मों, औद्योगिक सहकारी कलाओं और कामगारों की उपभोक्ता समितियों के रूप में समूह की सम्पत्ति मौजूद थी।[63] उत्तरी कोरिया में मामला ऐसा नहीं था। 'समाजीकरण' शब्दवली का उपयोग समूह की सम्पत्ति या उन मध्यम पूंजीपति वर्ग की सामूहिक सम्पत्ति के लिए किया जाता था जिनकी सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जाता था। ऐसा विशिष्ट तर्क दिया जाता था कि राष्ट्रीय पूंजी के अन्तर्गत समूह सम्पत्ति के निर्माण ने उन्हें 'समाजवादी कार्यरत जनता' में बदल दिया है।[64] राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को भविष्य में साम्यवादी समाज में शामिल कर लिया जाएगा।[65]

इस सबकी तार्किक निष्पत्ति यही थी, जैसा कि पहले चीन और यूगोस्लाविया में किया गया था, कि ग्रामीण बुर्जुआ को सामूहिक फार्मों में शामिल कर लिया जाएगा। कोरिया में कृषि सहकारिता के समय, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण आबादी के कुल हिस्से का 40 प्रतिशत गरीब किसान थे, मध्यम किसान 59.4 प्रतिशत और कुलकों को 0.6 प्रतिशत के असामान्य रूप से छोटे आंकड़े पर वर्गीकृत किया गया था। 1956 अन्त में, सकल ग्रामीण आबादी में 80.9 प्रतिशत परिवार सहकारी समितियों में शामिल हो चुके थे। कुछ वर्ग सहकारी समितियों से बाहर रह गए थे, जैसे कि सम्पन्न किसान, व्यापार और खेती में लगे किसान, पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए किसान और नव–मुक्त क्षेत्रों के किसान। अगस्त 1958 में 'समाजवादी' कृषि का आन्दोलन पूरा कर लिया गया था। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के समानांतर कुलकों ने भी अपने को 'फिर से ढाला' ताकि वे भी अपने आपको 'समाजवादी कार्यरत जनता' की श्रेणी में बदल सकें।[66]

एक क्षेत्र ऐसा भी था जहां उत्तरी कोरिया की जनता स्टालिन के बाद के समय में उत्पादन के साधनों का वस्तुकरण करने की आम अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास के विरूद्ध थे। सोवियत संघ में कृषि उत्पादन में सामूहिक फार्मों की मदद करने के लिए 1928 में मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों की स्थापना की गई थी। ये मशीन ट्रैक्टर स्टेशन (एमएसटी) उत्पादन के सामाजिक साधनों का एक हिस्सा थे जो सामूहिक खेतों में काम करने वाले किसानों के साथ काम करते थे और उनका मार्गदर्शन करते थे।[67] समाजवाद के मातहत सामूहिक खेती समूह सम्पत्ति के एक रूप का प्रतिनिधित्व करते थे। सोवियत संघ और यूरोप में उसके सहयोगियों (पीपुल्स अल्बानिया को छोड़कर) और पीपुल्स चीन में मशीन ट्रैक्टर स्टेशन को 1958 में समाप्त कर दिया गया, जिसने वहां की अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग मालों के परिचालन (कमोडिटी सरकुलेशन) के क्षेत्र को मजबूत किया। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 1950 में सोवियत सहयता से सहकारी खेती में उपयोग के लिए मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों की स्थापना की गई और वहां ट्रैक्टर तथा अन्य मशीनें लाई गईं, जिससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कुलकों की भूमिका को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। युद्ध काल में फार्म मशीन किराये के स्टेशनों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई और वे 1956 से 1960 के बीच उनकी संख्या आगे और दुगनी हो गई।[68] यह दिलचस्प बात है कि कि अगस्त 1958 में किम इल सुंग ने निजी तौर पर सोवियत संघ में मशीन टैक्टर स्टेशनों को ख्रुश्चेव द्वारा खत्म करने की आलोचना की थी और तर्क दिया था कि जनता की राजकीय सम्पत्ति को सहकारी समितियों को सौंपना साम्यवाद में संक्रमण की आवश्यकता के विपरीत था।69

"सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौर में अर्थशास्त्र और राजनीति" में लेनिन यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वर्गों के पूरी तरह उन्मूलन हो जाने तक सर्वहारा के अधिनायकत्व को बनाए रखना आवश्यक है।70 उन्होंने लिखा कि भूस्वामी और पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकना एक अपेक्षाकृत सरल काम था। जो ज्यादा कठीन काम है वह है वर्गों को खत्म करना और उस भिन्नता को खत्म करना जो कारखाने के मजदूरों और किसानों के बीच के पाया जाता है और उन सभी को मजदूर बनाना। सर्वहारा के अधिनायकत्व के काल में वर्ग अनिवार्यतः बने रहते हैं क्योंकि वे नहीं होंगे तो यह कैसे सम्भव है कि उन्हें खत्म किया जाए। एक बार जैसे ही वर्गों का उन्मूलन हो जाएगा, सर्वहारा के अधिनायकत्व का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने के द्वारा सर्वहारा वर्ग ने वर्गों के उन्मूलन की दिशा में सबसे

निर्णायक कदम उठाया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य सत्ता के तंत्र का इस्तेमाल करते हुए तथा उखाड़ फेंके गए बुर्जुआ और ढुलमुल पेट्टी बुर्जुआ का मुकाबला करने, उन्हें प्रभावित करने और उन पर दबाव बनाने के विभिन्न तरीकों को प्रयुक्त करते हुए सर्वहारा को अपना वर्ग संघर्ष जारी रखना होगा।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) और यूगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 1948 में विवाद उस समय उठा खड़ा हुआ जब यूगोस्लाविया जनता के जनवाद के दूसरे चरण, यानी कि, समाजवाद में संक्रमण के प्रति उदासीन रूख दिखा रहा था। इस हेतु आवश्यक था कि यूगोस्लाविया नए चरण में सर्वहारा के अधिनायकत्व का कार्यभार सम्पन्न करे। यह केवल संयोग नहीं था कि स्टालिन और मोलोटोव ने टीटो और कार्देलज के साथ अपने पत्राचार में बर्नस्टीन, वोल्मार और बुखारिन का उल्लेख किया था। बर्नस्टीन की पहचान इस दृष्टिकोण हेतु की गई थी कि समाजवाद स्वयं पूंजीवाद के द्वारा लाया जाएगा। वोल्मार जर्मनी की सामाजिक जनवाद के दक्षिणपंथ के धारा के थे, जो पार्टी के कृषि कार्यक्रम को विकसित करने के दौरान सम्पन्न किसानों के हितों की रक्षा कर रहे थे और जोर देकर कह रहे थे कि ग्रॉसबाउर्न, कुलक, देहात में समाजवादी निर्माण में सहायक बन सकते हैं। बुखारिन ने मेहनतकश किसानों पर आधारित कृषि के सामूहिकीकरण की पार्टी नीति का विरोध किया था। उनकी समझ यह थी कि कुलक वर्ग के सहयोग से सोवियत संघ में समाजवाद का निर्माण सम्भव है ; और यह कि कुलक बाजार के आधार पर उद्योगीकरण करना आवश्यक है। यह स्पष्ट था कि यूगोस्लाविया का नेतृत्व धनी किसान बुर्जआ वर्ग के अर्थिक रूप से उन्मूलन के विरूद्ध था। जब उन्हें सामूहिकीकरण करने के लिए बाध्यता महसूस हुई तब भी उन्होंने 'सामूहिक फार्मो' में कुलकों को शामिल किया। 1953 के पश्चात चीन और कोरिया के लिए यह मिसाल बन गया था। यूगोस्लाविया के नेतृत्व की अन्तर्राष्ट्रीयतावादी समाजवाद से प्रति इतनी शत्रुता थी कि उसके समर्थकों को कुख्यात गोली ओटेक जैसे हिरासत गृहों में बंदी रखा गया। कोमिन्टर्न ने 1949 के अपने प्रस्ताव में फैसलाकुन ढंग से घोषणा किया कि यूगोस्लाविया ने जनता की जनवादी व्यवस्था की हत्या कर दी है और वे अमेरिकी साम्राज्यवाद के खेमे में शामिल हो गए हैं, जबकि आंतरिक तौर पर उन्होंने एक पुलिस राज की स्थापना कर ली है, जिसमें देहातों में उनका सामाजिक आधार कुलक हैं और शहरों में पूंजीवादी तत्व हैं। राजकीय क्षेत्र अब जनता की सम्पत्ति नहीं है क्योंकि राज्य सत्ता अब जनता के शत्रुओं के हाथ में है।[71]

स्टालिन के बाद की अवधि में समाजवाद और साम्यवाद के निर्माण के लिए सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को बुलन्द रखने का सवाल अब राज्य सत्ता पर काबिज अधिकांश कम्युनिस्ट और वर्कर्स पार्टियों के लिए वांछनीय नहीं रह गया था। पीपुल्स अल्बा. निया इस रूझान का एक अपवाद रहा और यह एकमात्र जनता का जनवादी राज्य बन गया जिसने समाजवाद की स्थापना की। सामान्य तौर पर समाजवादी राज्य और जनवादी राज्य के बीच अन्तर करना अनिवार्य नहीं माना जाता था। अब ख्रुश्चेव 1956 में सीपीएसयू की बीसवीं कांग्रेस में एक नहीं, बल्कि अनेक समाजवादी देशों का जिक्र करते हैं।72 उन्होंने इस प्रश्न पर 1947–52 के जदानोव, स्टालिन और मैलेन्कोव की समझ को उलट दिया। इसी तरह, यूगोस्लाविया, जिसने जनता की जनवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया था, अब कथित 'समाजवादी खेमे' में शामिल हो गया था। अब जनता के जनवादी राज्यों जहां सर्वहारा का अधिनायकत्व मौजूद था और जहां राज्य सत्ता अब भी सर्वहारा और किसानों के अधिनायकत्व के स्तर पर थी, के बीच विभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। न ही अब समाजवादी माने जाने के लिए कृषि के सामूहिकीकरण को पूरा करने या कृषि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण को पूरा करने की कोई दबावपूर्ण अनिवार्य जरूरत रह गई थी। ख्रुश्चेव और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के उदारमना सूत्रीकरण ने 'समाजवाद' को पश्चिम में जनता के जनवादी राज्यों के स्तर पर ला दिया, जो मुख्यतः बाजार अर्थव्यवस्थाओं के गठन और साथ ही उन पूरब के जनता के जनवादों की ओर संक्रमण कर रहे थे जिन्होंने सर्वहारा के अधिनायकत्व के कार्यों को करने से या राष्ट्रीय बुर्जुआ और किसान बुर्जुआ को आर्थिक रूप से समाप्त करने से इन्कार कर दिया था। जनता के जनवादी राज्यों ने खुशी–खुशी इस पदवी को स्वीकार कर लिया कि वे अब समाजवादी राज्य हैं।

टिप्पणियां

1 जोस डियाज़, ''स्पेनिश लोगों की जीत के लिए आयोजन'', कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, मई, 1937, जोस डियाज़ पुरालेख https://www-revolutionarydemocracy-org/archive/diaz5&1937-pdf

जोस डियाज़, 'ट्रेस एनोस डी लुचा', एडिकियोनेस एस्पाना पॉपुलर, मेक्सिको, जूलियो डी 1942, पृष्ठ 500

2 टी.वी. वोलोकिटिना, जी.पी. मुराश्को, और ए.एफ. नोस्कोवा, ''नरोदनाया डेमोक्रातिया : मिफ इली रीयलनोस्ट?'' ओब्शचेस्टवेनो–पोलिटिचस्की प्रोत्सेसी वी वोस्टोचनोई एवरोप 1944–1948'', मोस्कवा, ''नौका'', 1993, सी. 3

3 माओ त्से–तुंग, द न्यू स्टेज, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के छठे विस्तारित प्लेनम को रिपोर्ट, नई चीन सूचना समिति, चुंगकिंग, 1938, पृष्ठ 21, 33–4,

42, 49, 50, 55; फरवरी 1938 में एसोसिएटेड प्रेस के संवाददाता श्री वांग कुंग–ताह को माओ त्से–तुंग द्वारा दिया गया साक्षात्कार, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, वॉल्यूम में पुनः प्रस्तुत किया गया, खण्ड ग्याहर, नंबर 2, सितम्बर 2005;

चीनी क्रांति और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, दिसंबर 1939, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, एन.डी.;

चीन का नया जनवाद, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, तीसरा संस्करण, जून, 1950, पृ. 5.

4 जॉर्जी दिमित्रोव, ''बल्गेरियाई वर्कर्स पार्टी (कम्युनिस्ट) की पांचवीं कांग्रेस के लिए केन्द्रीय समिति की राजनीतिक रिपोर्ट'', 19 दिसंबर, 1948, जॉर्जी दिमित्रोव पुरालेख www-revolutionarydemocracy-org

5 माओ त्से–तुंग, पीपुल्स डेमोक्रेटिक तानाशाही पर, माओ त्से–तुंग पुरालेख, https://www-revolutionarydemocracy-org/archive/MaoPPD2-pdf

6 चीन में पीपुल्स डेमोक्रेसी पर जे. वी. स्टालिन, 22 फरवरी 1950, https://revolutionarydemocracy-org/archive/pdchina-htm

7 ए. आई. सोबोलेव, पीपुल्स डेमोक्रेसी, समाज के राजनीतिक संगठन का एक नया रूप, फॉरेन लैंग्वेजेज पब्लिशिंग हाउस, मॉस्को, 1954, https://www-revolutionarydemocracy-org/archive/sobolev-htm

8 यह खंड ''मध्य और दक्षिण–पूर्वी यूरोप में साम्राज्यवाद–विरोधी, सामंतवाद–विरोधी क्रांतियों'' पर आधारित है

9 ए. आई. सोबोलेव, उपरोक्त; सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के राज्य स्वरूप पर लेनिन और स्टालिन; डी.आई. कम्युनिस्ट (बॉम्बे) में चेस्नोकोव, नंबर 2, फरवरी–मार्च 1950

10 ए. सोबोलेव, ''पीपुल्स डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी'', बोल्शेविक नंबर 19, अक्टूबर, 1951, कम्युनिस्ट रिव्यू, लंदन, जनवरी, 1952, पृष्ठ 3–21 में मुद्रित, https://www-revolutionarydemocracy-org/archive/sobolev2-htm

11 ए. ज़दानोव, द इंटरनेशनल सिचुएशन, फॉरेन लैंग. वेजेज पब्लिशिंग हाउस, मॉस्को, 1947, पृ. 9.

12 ''शांति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, श्रमिक वर्ग एकता के लिए संघर्ष'', नवंबर 1949 में हंगरी में आयोजित कम्युनिस्ट और वर्कर्स पार्टियों के सूचना ब्यूरो की बैठक के संकल्प और रिपोर्ट, पृष्ठ 2, https://www-revolutionarydemocracy-org/archive/cominform-pdf

13 जी. मैलेनकोव, सी.पी.एस.यू. की केंद्रीय समिति के कार्य पर उन्नीसवीं पार्टी कांग्रेस को रिपोर्ट, (बी.), अक्टूबर 5, 1952, फॉरेन लैंग्वेजेज पब्लिशिंग हाउस, मॉस्को, 1952, पृ. 7. https://www-marÛists-org/reference/archivestalin/works/1951/vkfFkZd&problems@ch06-htm

14 मैलेनकोव, उपरोक्त., पृ. 15–16.

15 रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल रिलेशं, सोवियत –यूगोस्लाव विवाद, आरआईआईआर, लंदन, नवंबर 1948, पृष्ठ 16

16 वही, पृ. 42.

17 उपरोक्त

18 यूगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी में स्थिति के संबंध में सूचना ब्यूरो का संकल्प, 28 जून 1948, उक्त, पृ. 66

19 ''एग्रीकल्चरल आर्टेल के मॉडल क़ानून'', इंप्रेकोर, खण्ड 15, क्रमांक 13, 23 मार्च 1935, पृ. 370

20 ''हत्यारों और जासूसों की शक्ति में यूगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी'', सूचना ब्यूरो का संकल्प (1949), शांति के लिए संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, श्रमिक वर्ग एकता, पीपीएच, बॉम्बे, 1950, https://www-revolutionarydemocracy -org/archive/cominform-pdf

21 पेट्रो रसिक, यूगोस्लाविया में कृषि विकास, प्रचार और प्रकाशन उद्यम यूगोस्लावजा, बेग्राड, 1955, पृ. 43, 46, 47

22 बोलेस्लाव बेरुत, ''पोलिश पार्टी लीडरशिप की गलतियों की जड़ें'', (1948)। रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, अप्रैल 2019, पृष्ठ 135–143; फ्रांत्सिशेक युज्यक (विटोल्ड), ''पोलिश वर्कर्स पार्टी के भीतर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी समूह पर विजय ने श्रमिक वर्ग की एकता और समाजवादी निर्माण की ओर मार्ग प्रशस्त किया है'', रूसी ''पोल्स्काया रोबोचाया पार्टिया वी बोर्बे'' से अनुवादित za natsionalnoe i sotsialnoe osvobozhdeniye, मॉस्को 1953, पीपी. 224–255, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, खण्ड पचीस, नम्बर 1, अक्टूबर, 2019, पृष्ठ 165–191

23 ''रुमानियाई वर्कर्स पार्टी में अधिकार विचलन के संबंध में दस्तावेज़'', रुमानियाई वर्कर्स पार्टी पब्लिशिंग हाउस, 1952, पीपल्स डेमोक्रेसी, रुमानिया, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी आर्काइव पर अनुभाग में, https://www-revolutionarydemocracy-org/archive/

24 जे.वी. स्टालिन, ''सोवियत अर्थशास्त्रियों के साथ पाँच वार्तालाप'', रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, खण्ड नौ, नम्बर 2,

सितम्बर 1998

25 पीपुल्स डेमोक्रेटिक तानाशाही पर, 1 जुलाई 1949, पेकिंग 1950, पृ. 8. https://www-revolutionarydemocracy-org/archive/MaoPPD2-pdf

26 उक्त., पृ. 6–7.

27 पूर्वोक्त, पृ. 8.

28 https://www-revolutionarydemocracy-org/archive.huai-htm

29 ''पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पहली वर्षगांठ'', ''स्थायी शांति के लिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी के लिए'', कम्युनिस्ट सूचना ब्यूरो का अंग, 29 सितम्बर, 1950, https://www-revolutionarydemocracy-org/archive/chinaA htm

30 ''श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच विरोधाभास चीन में प्रमुख विरोधाभास है'', माओ त्से–तुंग के चयनित कार्य, https://www-marÛists-org/reference/archive/mao/selected&works/volume&5/mswv5&21-htm

31 ए.आई. सोबोलेव, 1954, ऑप. सीआईटी. इस अनुभाग ने पूर्व में साम्राज्यवाद–विरोधी, सामंतवाद–विरोधी क्रांतियों का नेतृत्व किया, जोर जोड़ा गया

32 विजय सिंह, ''स्टालिन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में 'बाज़ार समाजवादश' का प्रश्न'8, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, खण्ड 1, क्रमांक 1, अप्रैल 1995

माओ त्सेतुंग के 33 चयनित कार्य, खंड। वी, पेकिंग, 1977, पृ. 297

34 https://www-marÛists-org/reference/archive/mao/selected&works/volume&5/mswv5&37-htm

35 https:/www-marÛists-org/reference/archive/mao/selected&works/volume&5/mswv5&37-htm

36 कुआन ता–तुंग, चीन में पूंजीवादी उद्योग और वाणिज्य का समाजवादी परिवर्तन, विदेशी भाषा प्रेस, पेकिंग, 1960, पृष्ठ 127–8। महत्व जोड़ें

37 पूर्वोक्त, पृष्ठ 24

38 वही, पृष्ठ 82

39 वही, पृष्ठ 56.

40 जॉर्जी दिमित्रोव, ''बल्गोरियाई वर्कर्स पार्टी (कम्युनिस्ट) की पांचवीं कांग्रेस के लिए केंद्रीय समिति की राजनीतिक रिपोर्ट;;, 19 दिसंबर 1948। जॉर्जी दिमित्रोव पुरालेख, www-revolutionarydemocracy-org

41 के. मार्क्स और एफ. एंगेल्स, सेलेक्टेड वर्क्स, लंदन, 1968, पृ. 645.

42 ''एग्रीकल्चरल आर्टेल के मॉडल क़ानून'', इंप्रेकोर, वॉल्यूम – 15, क्रमांक 13, 23 मार्च 1935, पृ. 370.

43 माओ त्से–तुंग, ''चीन में वित्तीय और आर्थिक स्थिति में बेहतरी के लिए एक मौलिक मोड़ के लिए संघर्ष'', 6 जून 1950, न्यू चाइना इकोनॉमिक अचीवमेंट्स 1950–1952 में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन समिति द्वारा संकलित , विदेशी भाषा प्रेस, पेकिंग, 1952, पृ. 6.

44 ची एन, ''कृषि सहयोग : उपलब्धि का एक रिकॉर्ड'', पीपल्स चाइना, अक्टूबर, 1956, पृ. 13

45 जे.वी. स्टालिन, यूएसएसआर में समाजवाद की आर्थिक समस्याएं, मॉस्को, 1952, पृ. 101

46 जी. मैलेनकोव, ''सी.सी. के कार्य पर 19वीं कांग्रेस को रिपोर्ट'' सीपीएसयू (बी)श, मॉस्को, 1952, पीपी. 75–76

47 सीपीएसयू का इतिहास, मॉस्को, एन.डी., दूसरा संशो. धित संस्करण, पृष्ठ 670.

48 माओ त्से–तुंग, ए क्रिटिक ऑफ सोवियत इकोनॉमिक्स, न्यूयॉर्क, 1977, पृष्ठ 144–5

48 एन.एस. ख्रुश्चोव, ''सी.सी. की रिपोर्ट'' सीपीएसयू की 20वीं पार्टी कांग्रेसश, मॉस्को, 1956, पृ. 43

49 ए. आई. सोबोलेव, उपरोक्त

50 एफ. आई. शबशीना, कोरिया : द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मुक्ति के लिए औपनिवेशिक लोगों का संघर्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्वानों की परिषद और एकेडमी ऑफ साइंसेज, यूएसएसआर के पेसिफिक इंस्टीट्यूट के संयुक्त सत्र की रिपोर्ट, को समर्पित द्वितीय विश्व युद्ध, 1949 के बाद राष्ट्रीय और औपनिवेशिक आंदोलन की समस्याए, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, बॉम्बे, एन.डी., पृष्ठ 81–2 द्वारा प्रकाशित

51 किम हान गिल, कोरिया का आधुनिक इतिहास, विदेशी भाषाएँ प्रकाशन गृह, प्योंगयांग, कोरिया, 1979. पृष्ठ 169–184

52 पूर्वोक्त, पृ. 191.

53 किम ब्योंग सिक, मॉडर्न कोरियारू द सोशलिस्ट नॉर्थ, रिवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स इन द साउथ एंड यूनिफिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1970, पृष्ठ 37

54 ''ई. पिगुलेव्स्काया, कोरेस्कीये नरोद वी बोरश्बी प्रोटिव

इम्पीरियलिस्टिकशेसिख एग्रेसोरोव'', ''एकेडेमिया नौक एसएसएसआर, इंस्टिट्यूट इकोनोमी,'' ''उग्लुब्लेनी क्रिसिसा कोलश्ओनियलनोय सिस्टमी इम्पीरियलिज्म पोस्ले मिरोवोई वोइनी'', गोसिजपोलिट, मोस्कवा, 1953, सी. 149. वही, पृष्ठ 47

55 वही. पृष्ठ 47.

56 किम इल सुंग, ऑन ज्यूचे इन आवर रिवोल्यूशन, खंड 1, एफएलपीएच, प्योंगयांग, 1975, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफल पूर्ति के लिए, 6 मार्च 1958, पृष्ठ 215.

57 उपरोक्त

58 ''पूंजीवाद से समाजवाद और सर्वहारा की तानाशाही में संक्रमण की अवधि के प्रश्नों पर'', 25 मई, 1967, किम इल सुंग, वर्क्स, वॉल्यूम। 21, एफएलपीएच, प्योंगयांग, 1985, पीपी. 228–232

59 किम ब्योंग सिक, उपरोक्त पृष्ठ 78–79

60 पूर्वोक्त, पृष्ठ 79

61 उपरोक्त, पृष्ठ 47

62 किम हान गिल, उपरोक्त, पृष्ठ 387

63 राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यू.एस.एस.आर. के विज्ञान अकादमी के अर्थशास्त्र संस्थान द्वारा जारी एक पाठ्यपुस्तक, (1955 संस्करण), लॉरेंस और विशार्ट, लंदन, 1957, पृष्ठ 524.

64 किम इल सुंग, ''डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक हमारे लोगों के लिए स्वतंत्रता और आजादी का बैनर है...'', चयनित कार्यों में, खंड 5; प्योंगयांग; 1975; पृष्ठ 151

65 किम इल सुंग, ''आइए हम अपने देश की समाजवादी व्यवस्था को और मजबूत करें'', चयनित कार्यों में, खंड 6, प्योंगयांग; 1975, पृष्ठ 317

66 किम हान गिल, उपरोक्त, पृष्ठ 383–5

67 ''क्रतकी इकॉनोमिकहेस्की स्लोवरश मोस्कवा, गोसुडारस्टवेनोइ इज़दत'', एल्स्तवो पॉलिटिचस्कोई साहित्य, 1958., पृष्ठ 169–70

68 किम हान गिल, उपरोक्त, पृष्ठ 243, 332. किम इल सुंग, ''ऑन ज्यूचे इन अवर रिवोल्यूशन'', खण्ड 1, एफएलपीएच, प्योंगयांग, पी. 252

69 आदरणीय किम जोंग इल, उत्तर कोरियाई नेता की आधिकारिक जीवनी, ओबराराव पब्लिशिंग हाउस, मिलानो, 2005, पृष्ठ 118–119

70 वी.आई. लेनिन, कलेक्टेड वर्क्स, खण्ड 30, प्रोग्रेस पब्लिशर्स, मॉस्को, दूसरी प्रिंटिंग, 1974, पृष्ठ 107–117

71 शांति के लिए संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, श्रमिक वर्ग एकता, पीपीएच, बॉम्बे, 1950, उपरोक्त, पृष्ठ 49 https://www-revolutionarydemocracy-org/archive/cominform-pdf ih- 62-

72 ग ग एस'एज़्ड, कोमुनिश्चेस्कॉय पार्टि सोवियतस्कोगो सोयुज़ा, स्टेनोग्राफिचेस्की ओटचेट, टॉम 1, गोसुडारस्टेवेनो इज़्डाटेलस्टो पोलिटिचेस्कोय लिटरेचरी, मॉस्को, 1956, सी–13, इसके बाद ए. आई सोबोलेव ''शक्तिशाली समाजवादी शिविर'' का उल्लेख करते हैं, देखें : ''पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के कुछ रूप'', दिल्ली, 1956, www-revolutionarydemocracy-org